

जयराम रमेश के सितारे गर्दिश में हैं केवल सोनिया गांधी का प्रभाव उन्हें बचाये हुए है

पहले जब मल्लिकार्जुन खड़गे उनकी छुट्टी करने वाले थे, ए.आई.सी. सी. मुख्यालय से तो राहुल गांधी ने उन्हें बचाया था

- रेणु मित्तल -

- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -
नई दिल्ली, 6 मई। ए आई सी सी महासचिव के रूप में जयराम रमेश का मीडिया प्रभारी पद का प्रभार अथरखूल में प्रतीत हो रहा है।

सूत्रों का कहना है कि उन्हें सोनिया गांधी का समर्थन एवं आशीर्वाद प्राप्त है। उन्हें जब भी अपने ऊपर कोई गाज गिरती महसूस होती है, वे जाकर सोनिया गांधी से मिलते हैं और वे हर बार उनके साथ खड़ी हो जाती हैं।

अभी पिछले सप्ताह ही, जातिगत जनगणना के लिए सहमत हो जाने के प्रधानमंत्री के निर्णय के बाद, राहुल गांधी ने 24, अकबर रोड पर अपनी प्रैस कॉन्फ्रेंस आयोजित की थी। उन्होंने कॉन्फ्रेंस से जाते समय जयराम पर कटाक्ष किया था: “आप तो घटनाक्रम के इस मोड़ पर बड़े परेशान हो रहे होंगे।”

यह सर्वविदित है कि रमेश जातिगत जनगणना के विचार के विरोध में थे तथा जातिगत जनगणना का अनिच्छा से समर्थन कर रहे थे।

■ राहुल गाँधी ने भी यह महसूस कर लिया है कि, जयराम रमेश, गलत आदमी हैं, मीडिया के मामले में, तो अब सोनिया गांधी के कारण उनकी नौकरी बरकरार है।

■ यह कोई छुपी हुई बात नहीं है, कि जयराम रमेश जातिगत मतगणना के खिलाफ हैं, अतः उन्होंने ए.आई.सी.सी. के मीडिया इंचार्ज होते हुए भी कोई प्रयास नहीं किया पार्टी का पक्ष पत्रकारों के समक्ष रखने के लिए।

■ राहुल गांधी चाहते थे, जाति मतगणना के मामले में कांग्रेस की भूमिका को हाई-लाईट करने के लिए देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित हों, पर जयराम रमेश ने राहुल गांधी के इरादे को जनता के समक्ष लाने के लिए कुछ काम नहीं किया, उनकी यह ही भूमिका अहमदाबाद सेशन के दौरान रही।

■ जयराम रमेश के खिलाफ यह बात भी खूब प्रचारित हो रही है, कि, जयराम रमेश, अभित शाह के भारी प्रशंसक हैं, और कई मुद्दों पर शाह की सार्वजनिक रूप से तारीफ करते रहे हैं।

जब राहुल गांधी ने उनसे यह सुनिश्चित करने को कहा कि इस मुद्दे पर पूरे देश में प्रैस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जायें, तो जयराम ने उनके इस निर्देश की अनुपालना नहीं की थी।

अगले दिन जयराम को इस मुद्दे पर प्रैस से बात करनी थी लेकिन उनके पास कहने के लिए कोई नई बात थी ही नहीं, इसलिए उन्होंने सिर्फ वही सब दोहरा दिया, जो राहुल गांधी ने एक दिन पहले अपनी प्रैस ब्रीफिंग में कहा था। बाद में, यह एक ऑन-द-रिकॉर्ड डीब्रीफिंग बन गई।

कोई भी व्यक्ति यह अनुमान लगा सकता है कि वह सब क्या है। काश! कोई उन पर मेहरबानी कर दे और उन्हें बता दे कि डीब्रीफिंग क्या होती है।

हाल ही में अहमदाबाद में हुए ए आई सी सी अधिवेशन में, जयराम दिन भर स्टेज पर बैठे दिखाई देते रहे, लेकिन उन्होंने बंधुआ मीडिया को अंदरूनी पॉइंट्स के बारे में पता करने, और यहां तक कि अधिवेशन पर डीब्रीफिंग की (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

‘आईओसी 4 सप्ताह में सीतापुरा प्लांट शिफ्ट करने का प्लान बनाये’

जयपुर, 6 मई। राजस्थान हाईकोर्ट ने शहर सीतापुरा स्थित एलपीजी बॉटलिंग प्लांट को सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया से दूसरी जगह शिफ्ट करने के संबंध में आईओसीएल (इंडियन ऑइल कार्पोरेशन लिमिटेड) से चार सप्ताह में प्लान बनाने के लिए कहा है। वहीं मामले

■ हाईकोर्ट ने कहा कि मौजूदा समय में यह बॉटलिंग प्लांट रिहायशी कॉलोनिyों, अस्पतालों, स्कूल व कॉलेजों के लिये खतरा बन गया है।

में पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन को भी पक्षकार बनाए जाने के लिए कहा है। सीजे एमएम श्रीवास्तव व जस्टिस मुकेश राजपुरोहित ने यह आदेश ओमप्रकाश टांक की जनहित याचिका पर दिए। सुनवाई के दौरान सीजे ने भंकरोटा के पास हुए एलपीजी टैंकर ब्लास्ट मामले का हवाला देते हुए कहा (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले को सजा सुनाई

जयपुर, 6 मई। जयपुर महानगर प्रथम के सत्र न्यायालय ने सांगानेर इंटरनेशनल एयरपोर्ट में बम धमाका करने का धमकी भरा ईमेल भेजने वाले युवक धर्मपाल बिजारणियां को छह माह की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने 19 वर्षीय इस अभियुक्त पर दो हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना राशि अदा नहीं करने पर अभियुक्त को पन्द्रह दिन अतिरिक्त जेल में रहना होगा। पीठासीन अधिकारी नंदिनी व्यास ने अपने आदेश में कहा कि जांच अधिकारी ने अभियुक्त युवक की

■ गत वर्ष 15 और 16 फरवरी को अभियुक्त धर्मपाल ने ई-मेल भेजकर अलग-अलग समय जयपुर एयरपोर्ट पर बम विस्फोट की धमकी दी थी।

ओर से अपने मोबाइल में प्रयुक्त की जा रही सिम से यह धमकी भरा मेल भेजा जाना प्रमाणित माना है। एयरपोर्ट से देश-विदेश में उड़ानें जाती है। ऐसे धमकी भरे ईमेल से इनका संचालन प्रभावित होने की संभावना रहती है और आम जन में भी भय उत्पन्न होता है।

अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक लियाकत खान ने अदालत को बताया कि मामले में टर्मिनल मैनेजर मयंक सोटी ने 23 फरवरी, 2024 को एयरपोर्ट थाने में रिपोर्ट दी थी। रिपोर्ट में (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

मेन लाइन टी.वी. चैनल की तुलना में यू-ट्यूब चैनल काफी कष्टदायक लग रहे हैं

कई यू-ट्यूब चैनल को बन्द कराया सरकार ने

- रेणु मित्तल -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -
नई दिल्ली, 6 मई। मोदी सरकार आलोचना के मुद्दे पर और ज्यादा असहिष्णु बनती जा रही है। और अब राष्ट्रीय सुरक्षा एवं राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा के नाम पर यह बिना किसी नोटिस या चेतावनी के यू ट्यूब चैनल बंद कर रही है।

यू ट्यूब चैनल 4 पी एम को बंद कर दिया और कारण भी नहीं बताया गया कि इसे क्यों बंद किया गया।

और अब वरिष्ठ पत्रकार पुष्प प्रासून वाजपेयी का यू ट्यूब चैनल बिना किसी पूर्व सूचना के बंद कर दिया गया। “4 पी एम” के संजय शर्मा सुप्रीम कोर्ट चले गये तथा कोर्ट ने मोदी सरकार को नोटिस जारी करते हुए, 7 दिन के अन्दर इस बात का जवाब मांगा है कि इस चैनल को शट डाउन क्यों किया गया है।

यह देखना बहुत दिलचस्प होगा कि सरकार देश-हित और राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर अपने नियम के बचाव में क्या तर्क देती है।

सम्भवतः इस समय तथाकथित मेनलाइन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ही ऐसा मीडिया बचा है, जो देशभक्त है तथा

■ फोर पी.एम. यू-ट्यूब चैनल व वरिष्ठ पत्रकार पुष्प प्रसून बनर्जी के यू-ट्यूब चैनल को बन्द करवाया सरकार ने।

■ फोर पी.एम. यू-ट्यूब चैनल के मालिक संजय शर्मा, ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी पेश कर, उनकी चैनल बन्द करवाने के आदेश को चुनौती दी।

■ सुप्रीम कोर्ट ने इस अर्जी को सुनकर सरकार को नोटिस दिया, कि, सरकार साथ में जवाब दे कि, फोर पी.एम. चैनल को बन्द करने का क्या कारण है।

■ सरकार ने कुछ समय पहले पाकिस्तान के 14 यू-ट्यूब चैनल को बन्द करवाया था, पर ये चैनल अब फेसबुक पर जाकर अपनी बात कह रहे हैं।

अत्यंत संगीन मुद्दों पर सरकार के मत को दोहराता रहता है। इसके साथ ही, यह मीडिया सरकार से असुविधाजनक प्रश्न नहीं करता, तथा सरकार से संबंधित मुद्दों पर बहुत ही ज्यादा वफादार है और मोदी एण्ड कंपनी की प्रशंसा के पुल बांधने में सबसे आगे है।

इसे अब “गोदी मीडिया” कहा जा रहा है क्योंकि इसने के प्रति भक्ति के मामले में सबको पीछे छोड़ दिया है। यू ट्यूब चैनल ही तो ऐसे चैनल

बचे हैं, जो सवाल पूछ रहे हैं तथा सरकार के मत का आंख बंद कर समर्थन नहीं करते हैं।

आगामी दिनों में, यही देखना बाकी है कि और कितने चैनल बंद किये जायेंगे और कितने पत्रकार सरकार के अनुरूप चलने के लिए अथवा चैनल छोड़ने के लिए बाध्य किये जाते हैं। सरकार ने 14 पाकिस्तानी यू ट्यूब चैनल प्रतिबंधित कर दिये हैं तथा उनमें से कई फेसबुक (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

पूर्व एन.डी.ए. नेता ने राहुल को मुख्य अतिथि बनाया

महादेव जानकर, तालकटोरा स्टेडियम में राजमाता अहिल्या देवी होलकर की तीन सौवीं जयंती पर भव्य समारोह का आयोजन कर रहे हैं

-सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 5 मई। इसे, खास तौर से महाराष्ट्र में, राजनैतिक गठबंधनों के पुनर्निर्माण की शुरुआत माना जा सकता है कि महादेव जानकर, जो धनगर (गडेरिया) समुदाय के जाने-माने नेता, तथा भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सहयोगी हैं, ने आज दिल्ली में कांग्रेस नेता तथा लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष, राहुल गांधी से भेंट की।

जानकर, जो राष्ट्रीय समाज पार्टी (आरएसपी) के अध्यक्ष हैं, ने गांधी को 31 मई को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित एक समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है। यह समारोह पुण्यश्लोक राजमाता अहिल्या देवी होलकर की 300 वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है।

जानकर ने कहा, “उन्होंने (राहुल)

■ इस निमंत्रण को महाराष्ट्र में राजनीतिक दलों की बदलती वफादारी का प्रमाण माना जा रहा है।

■ महादेव जानकर को गोपीनाथ मुण्डे पार्टी में लेकर आये थे, तथा उन्हें देवेन्द्र फड़नवीस के प्रथम शासन काल में मंत्री भी बनाया गया था।

■ पर मुण्डे की मृत्यु के बाद, उन्हें महत्व नहीं मिल रहा था, अतः उनकी कांग्रेस से जुड़ने की काफी चर्चा है।

आमन्त्रण प्राप्त होने पर अत्यन्त प्रसन्नता व्यक्त की तथा समारोह में शामिल होने की सहमति दे दी।” जानकर ने आगे कहा, “अब हम एनडीए का हिस्सा नहीं हैं। भाजपा ने मेरा इस्तेमाल किया और फिर मुझे उपेक्षित कर दिया। मैं ऐसे बड़े कोमती सबक सिखाने के लिये एनडीए का आभारी हूँ। मैं रेखाल से, अब वह समय आ गया है कि मैं अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने पर ध्यान दूँ।”

धनगर समुदाय के नेता जानकर

अन्यत्र विलय करना उचित नहीं समझा तथा परभनी सीट से 2024 का लोकसभा चुनाव हार जाने के बाद, एनडीए को छोड़ देने का निर्णय ले लिया। महाराष्ट्र के शोलापुर, सांगली, बारामती, परभनी तथा सतारा लोकसभा चुनाव क्षेत्रों में धनगर समुदाय के लोग अच्छी –खासी संख्या में हैं तथा 25–30 से अधिक विधानसभा सीटों के नतीजों को प्रभावित कर सकते हैं।

जानकर ने कहा, “मैंने महाराष्ट्र में कांग्रेस के साथ राजनैतिक गठजोड़ करने का निर्णय अभी तक नहीं लिया है। कोई निर्णय लेने में समय लगेगा, क्योंकि कुछ विचार-विमर्श तथा सलाह-मशविरें करने होंगे। लेकिन हमारा लक्ष्य राजनैतिक रूप से आगे बढ़ना है तथा इसके लिये जो भी जरूरी होगा, वह करेंगे।” उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर जातिगत जनगणना की सफलतापूर्वक माँग करने (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

ईरान के विदेश मंत्री आज भारत में

नयी दिल्ली, 06 मई। ईरान के विदेश मंत्री सैय्यद अब्बास आरगची बुधवार को भारत की दो दिन की यात्रा पर यहाँ आ रहे हैं।

विदेश मंत्रालय के अनुसार डॉ. आरगची कल दोपहर नयी दिल्ली पहुंचेंगे तथा गुरुवार को वह दोपहर में हैदराबाद हाउस में विदेश मंत्री एस जयशंकर के

■ पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव के बीच ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास आरगची की भारत यात्रा को कूटनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

साथ बैठक में शामिल होंगे। वह अपराह्न चार बजे वह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भेंट करेंगे और रात में स्वदेश लौट जाएंगे।

जम्मू-कश्मीर में पहलगाام आतंकवादी हमले के बाद भारत की पाकिस्तान पर सामरिक कार्रवाई की तैयारियों के बीच ईरान के विदेश मंत्री की (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

भारत व इंग्लैण्ड ने ‘‘फ्री ट्रेड डील’’ पर हस्ताक्षर किये

टैरिफ वॉर की अनिश्चितता से तंग आकर दोनों देशों ने आपस में व्यापार करने के लिए यह समझौता किया है

■ इस समझौते पर तीन साल से बातचीत चल रही थी, पर, किसी न किसी कारण फाइनल नहीं हो पा रही थी। पर टैरिफ वॉर के दबाव ने इन दिक्कतों को दूर करने में अच्छी भूमिका निभाई।

व्यापार बाधाओं को कम करते हुए मजबूत और सुरक्षित अर्थव्यवस्था बनाना है।

यह समझौता ऐसे समय में हुआ है, जब वैश्विक सप्लाय चेन भू-राजनीतिक तनावों से जूझ रही है और बहुपक्षीय व्यापार वार्ताएं (मल्टीलेटरल ट्रेड नैगोिएशन्स) सर्वसम्मति के लिए संघर्ष कर रही हैं। ऐसे में यह द्विपक्षीय समझौता, व्यावहारिक आर्थिक कूटनीति को आगे बढ़ाने की दोनों देशों की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भारत के लिए यह एफटीए एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसके बाद भारत-भित्र-भित्र ट्रेड पार्टनर

ले सकता है तथा ग्लोबल मैनुफैक्चरिंग व सर्विसेज हब बनने की अपनी महत्वाकांक्षा को मजबूत कर सकता है। वहीं, यू.के. के लिए, ब्रेक्सिट के बाद की व्यापार नीति में, यह एक महत्वपूर्ण प्रगति है, जो उसकी वैश्विक आर्थिक प्रासंगिकता को पुनः साबित करती है।

यूके सरकार के आंकड़ों के अनुसार, 2024 की चौथी तिमाही तक समाप्त चार तिमाहियों में वस्तुओं और सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार 42.6 बिलियन पाउण्ड था-जो पिछले वर्ष की तुलना में 8.3 प्रतिशत अधिक है। भारत का यूके को निर्यात 10.1

प्रतिशत बढ़कर 25.5 बिलियन पाउण्ड हो गया, जबकि यूके का भारत को निर्यात 5.8 प्रतिशत बढ़कर 17.1 बिलियन पाउण्ड पहुंच गया।

उम्मीद की जा रही है कि यह एफटीए व्यापार की इस गति को और तेज करेगा। भारत के लिए यह समझौता वस्त्र, दवाओं और सूचना प्रौद्योगिकी जैसे प्रमुख क्षेत्रों में नए अवसरों को जन्म देगा। भारतीय परिधान निर्यातकों को टैरिफ में कटौती से यूके के खुदरा बाजार में प्रतिस्पर्धा में बढ़त मिलेगी। फार्मा कंपनियों को ड्रग अप्रूवल (दवा अनुमोदन) प्रक्रिया में सरलता और इन्टरलैक्चुअल प्रॉपर्टी नियमों में स्पष्टता से लाभ मिलेगा।

भारत के खाद्य और कृषि उत्पाद, जैसे चाय, मसाले और बासमती चावल, ब्रिटेन के खुदरा बाजारों में अधिक स्थान बना सकेंगे, वहीं ऑटोमोबाइल पुर्जों के

क्षेत्र को भी सरल कस्टम नियमों और कम शुल्क से लाभ मिलेगा, जिससे यूके की मैनुफैक्चरिंग सप्लाय चेन्स के साथ समन्वय बढ़ेगा। ये लाभ भारत के “मेक इन इंडिया” अभियान का सीधे समर्थन करते हैं।

यूके के लिए इस समझौते में, स्कॉच व्हिस्की और वाइन जैसे मादक पेय पदार्थों पर लंबे समय से प्रतीक्षित टैरिफ कटौती भी है-जो कि वार्ताओं में बाधा बनते रहे हैं। ब्रिटेन के फायनैंशियल एवं लीगल सर्विस प्रोवाइडर्स को भी मार्केट तक बेहतर पहुंच और रैगुलेटरी अडचनों में कमी से लाभ होगा। यह समझौता शिक्षा क्षेत्र में सहयोग को भी प्रोत्साहित करेगा।

निवेश इस समझौते का प्रमुख पहलू है। यह एग्रीमेंट, भारत के स्वच्छ ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहनों और फिनटेक जैसे क्षेत्रों में भारत के बढ़ते बाजारों पर नजर रखने वाली ब्रिटिश फर्मों के लिए ‘रैगुलेटरी क्लेरिटी’ और कर स्थिरता प्रदान करता है। इसी प्रकार यूके में कार्यरत भारतीय व्यवसायों को भी अधिक स्थिर नियमों, कम अनुपालन (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

विधायक रिश्तत प्रकरण: पीए रोहित की तलाश जारी

जयपुर, 6 मई। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने बीस लाख रुपए की रिश्तत लेने के मामले में बांसवाड़ा के बागीदौर विधायक जयकृष्ण पटेल के पीए रोहित के मामा जसवंत उर्फ लक्ष्मण और उसके परिचित जगराम को मंगलवार को कोर्ट में पेश किया गया,

■ मंगलवार को पुलिस ने सवाई माधोपुर, वैंर, भरतपुर आदि स्थानों पर रोहित की तलाश में दबिश दी

जहां से उन्हें एक दिन की रिमांड पर सौंप दिया गया। विधायक जयकृष्ण पटेल और उसके चचेरे भाई विजय पटेल को एसीबी की टीमों ने मंगलवार को सवाई माधोपुर, वैंर भरतपुर सहित, उसके संभावित स्थानों पर दबिश दी।

ए.सी.बी., विधायक के पीए की तलाश में जुटी है। रोहित की तलाश में एसीबी की टीमों ने मंगलवार को सवाई माधोपुर, वैंर भरतपुर सहित, उसके संभावित स्थानों पर दबिश दी। (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

विचार बिन्दु

एकता चापलूसी से कायम नहीं की जा सकती। –महात्मा गाँधी

जाति संगठन सामाजिक सुधार नहीं, सत्ता में हिस्सेदारी चाहते हैं

भारतीय संसदीय लोकतंत्र की प्रतिस्पर्धी राजनीति में अभी जातियों का मुद्दा गरमाया हुआ है। एक बड़े फैसले में सरकार ने घोषणा की है कि अगली जनगणना में जाति की गणना को भी शामिल किया जाएगा। हालाँकि ऊपर से ऐसा लगता है कि यह मुद्दा वोटों की सामान्य राजनीति का है किन्तु इसके ऐसे निहितार्थ भी हैं जिस पर अकादमिक बहस हो सकती है। जातियाँ लंबे समय से भारतीय समाज में रही हैं, किन्तु उनके आधुनिक संगठन स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बने और पनपे। उस समय उन्हें सांस्कृतिक और सामाजिक जागृति के रूप में देखा गया। जातियों के संगठन आजादी के आंदोलन में राष्ट्रीय जागृति के रूप में अस्तित्व में आये। इनका मूल उद्देश्य अपने-अपने समुदायों की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मुक्ति तथा उत्थान था। लेकिन समय के साथ ये संगठन राजनीतिक दबाव समूहों के रूप में बदलते चले गए और जातिवाद भारतीय राजनीति का अभिन्न अंग बन गया। जाति की राजनीति ने देश में राजनीतिक और सामाजिक संघर्ष भी पैदा किए हैं। स्वतंत्रता के बाद जाति संगठन प्रतिस्पर्धी संसदीय लोकतंत्र में अपनी संख्या के बल पर राजनीतिक दलों और सरकार पर अपनी शर्तें थोपने लगे। इक्कीसवीं सदी के दूसरे दशक में तो अब जातिगत पहचान एक भयावह रूप ले रही दिखती है। ब्रिटिश शासन के दौरान आधुनिक शिक्षा के प्रसार, उद्योगों के उदय और विकास, रेलवे की शुरुआत, परिवहन और संचार के विकास, तथा शहरी विकास ने नये सामाजिक वर्गों को जन्म दिया। ऐसा लगा था कि नये सामाजिक वर्ग जाति व्यवस्था के उन्मूलन की राह प्रशस्त करेंगे। जाति व्यवस्था के उन्मूलन में अंग्रेजों की कोई दिलचस्पी नहीं रही। उनके लिये भारतीय समाज का जातियों में विभाजन उनके राज के स्थायित्व के लिये अनुकूल था। उन्नीसवीं सदी में पनपे धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलनों में पहली बार जाति व्यवस्था का खुल कर विरोध हुआ। आजादी के बाद भी जाति प्रथा के खिलाफ माहौल बना रहा जब धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलनों में जाति व्यवस्था की निंदा की गई और इसका विरोध किया गया। लेकिन राजनीतिक आंदोलनों के उभरने के बाद सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन कमजोर होते चले गये। कुछ अध्येता मानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मुख्य रूप से राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों पर तो ध्यान केंद्रित किया मगर जाति और जातिवाद की समस्या से निपटने के लिए कोई रणनीति नहीं बनाई जिससे देश में जाति राजनीति के उदय और विकास के लिए जगह बनती चली गई। एक समय ऐसा भी था जब लोगों ने अपने नामों से जाति का हवाला हटाय़ा। लंबे समय तक राजस्थान की राजनीति में प्रभावी भूमिका निभाने वाली कमला बेनीवाल ने अपने नाम से बेनीवाल हटा दिया था। परंतु जातियों के उन्मूलन के प्रयास कारगर नहीं हुए। प्रतिस्पर्धी निर्वाचन प्रणाली के चलते हालात इस हद तक पहुंच गये हैं कि लोकतांत्रिक जातिवाद और सामाजिक प्रक्रियाओं के प्रति आम जनता में जातिवाद बाधा बनने लगा है। देश की रियासतों के एकीकरण के साथ बने गणतांत्रिक भारत में जहां सामंती अभिजात वर्ग की राजनीतिक व्यवस्था प्रभावी रूप में मौजूद थी वहां उसकी जगह लोकतंत्र की स्थापना की प्रक्रिया आसान नहीं थी। वह प्रक्रिया पूरी होती उससे पहले ही जातिवाद ने राजनीतिक अवसरवाद, विचारहीन और सिद्धांतहीन राजनीति को पनपा दिया। अब तो ऐसा लगता है जातिवाद के सामने सभी मजबूर हैं क्योंकि चुनावी राजनीति में जातियाँ ऐसा मोहरा बन गई हैं, जिसे चला कर पार्टियाँ सत्ता पर कब्जित होने का खाब देखती हैं।

कुछ राज्य सरकारों ने अपने राज्यों में जातियों की गणना करने का प्रयास किया तो तुरंत ही, पेशानी शुरू हो गई। जैसे कर्नाटक ने 2017 में एक निस्पृत जाति और सामाजिक-आर्थिक जनगणना की। पारंपरिक रूप से यह माना जाता रहा है कि दो प्रमुख और शक्तिशाली जाति समूह- लिंगायत और वोक्कालिंगा - राज्य की आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा हैं। किन्तु लोक हुई जनगणना रिपोर्ट ने उस धारणा को उलट दिया है। एक समाचार रिपोर्ट के अनुसार जनगणना डेटा के अनुसार, कर्नाटक में दलितों और मुसलमानों के लिगायत लिगायतों और वोक्कालिंगाओं से अधिक है। राज्य में कुछ आबादी में अनुसूचित जातियों की हिस्सेदारी 19.5 प्रतिशत है, जो इसे सबसे बड़ी जाति इकाई बनाती है। इसके बाद मुसलमान आते हैं, जो आबादी का 16 प्रतिशत हिस्सा बनाते हैं। इन दो समूहों के बाद लिंगायत और वोक्कालिंगा आते हैं, जो क्रमशः '14 प्रतिशत और 11

भारत के संदर्भ में वर्ण-जाति को नस्लवाद के रूप में वर्णित करना, यहां की संस्कृति को खत्म करने की राजनीति का एक शक्तिशाली हथियार है। वे कहते हैं कि यदि कोई यह माने कि नस्लवाद हिंदू धर्म का अविभाज्य अंग है, तो फिर समझदारी यही होगी कि इस संकट से समाज को मुक्त कराने के लिए हिंदू धर्म से ही छुटकारा पा लिया जाए और ऐसा करने के लिए सभी को आपस में हाथ मिला लेना चाहिए।

पैदा कीं, जिन्होंने जाति को भारतीय समाज का केंद्रीय प्रतीक बना दिया। इस प्रतीक ने अपना काम बखूबी किया। जवाहरलाल नेहरू ने स्वीकार किया कि इसे दूर करने का कोई आसान तरीका नहीं है क्योंकि ऐसे सामाजिक रूपों की कल्पना करना आसान नहीं है जो जाति की भाषाओं से परे हों, जो रोजमर्रा की ज़िंदगी के अनुष्ठान, पारिवारिक, सामुदायिक, सामाजिक-आर्थिक, राजनीतिक और सार्वजनिक रंगमंचों में इतनी अंकित हो गई हैं। पश्चिम के लोगों के दिमाग में यह बैठ गया कि भारत में जातियाँ उनकी अपनी नस्लों की अवधारणा जैसी हैं। परिणामस्वरूप पश्चिमी अकादमिक लोगों की नजर में यह वैचारिक ढांचा भारतीय वर्ण और जाति को शोषण की प्रणाली बनाता कहा गया। शनैः शनैः पश्चिम के वैचारिक चरमवाले अकादमिक विद्वान वर्ण और जाति जाति व्यवस्था की तुलना पश्चिम में प्रचलित गुलामी और दास प्रथा जैसी व्यवस्थाओं से भी की करने लगे और इस देश की कई वर्तमान सामाजिक समस्याओं के लिए वर्ण और जाति को जिम्मेदार ठहराने लगे। इस अवधारणा का खंडन करने वालों का कहना है कि वैचारिक विमर्श में पश्चिम के अध्येताओं ने तीन बड़ी गलतियाँ कीं। वे यह मान कर चले कि भारत का विविध जातियों व श्रेणियों में विभाजित सामाजिक ढांचा पिछले हजारों वर्षों से अपरिवर्तनीय रहा है। वह जरा भी नहीं बदला है। दूसरे, वे वर्तमान समय की सभी प्रकार की सामाजिक समस्याओं का आधार प्राचीन काल की उत्पत्ति मान लेते हैं और भारतीय समाज की आज की समस्याओं के लिए वैदिक आधाराों को दोषी ठहरा देते हैं। यह सोच उनकी अपनी नस्लीय विगत के चरम से बनी है। तीसरे, ये अध्येता भारत के लंबे इतिहास में एक बार नहीं बल्कि बार-बार आए बड़े पैमाने पर व्यवधानों को नजरअंदाज कर देते हैं या उन पर अपने सोच का मुलम्मा चढ़ा देते हैं। ऐसे मानने वालों की संख्या अब बढ़ रही है। हार्दय में वर्ण-जाति को नस्लवाद के रूप में वर्णित करना, यहां की संस्कृति को खत्म करने की राजनीति का एक शक्तिशाली हथियार है। वे कहते हैं कि यदि कोई यह माने कि नस्लवाद हिंदू धर्म का अविभाज्य अंग है, तो फिर समझदारी यही होगी कि इस संकट से समाज को मुक्त कराने के लिए हिंदू धर्म से ही छुटकारा पा लिया जाए और ऐसा करने के लिए सभी को आपस में हाथ मिला लेना चाहिए। ऐसा व्यंग्य कसने वालों का दावा केवल वैचारिक ही नहीं है। हाल में ही ऐसी आवाज़ें भी आई हैं जो हिन्दू धर्म का समूल नाश चाहती हैं।

सच तो यह है कि भारतीय धर्मशास्त्र के कई कथन रूपक हैं, और उसके कई छंद गृह या अजेय हैं जिन्हें अध्येता अपनी-अपनी नजर से व्याख्यायित करते हैं। इनमें मार्क्सवाद की दृष्टि प्रमुख है। मूल मार्क्सवाद एक आर्थिक वर्ग सिद्धांत था जिसमें कहा गया था कि प्रत्येक समाज को आर्थिक रूप से उपीडडित और उपीडडनकारी के रूप में देखा जा सकता है। मार्क्स उन्हें धर्म या नस्ल के आधार पर अलग नहीं किया था जैसा कि उनके बाद उनके अनुयाइयों ने किया। मार्क्स के अनुसार केवल वे आर्थिक वर्ग जिनके पास उत्पादन के साधन नहीं थे, जो भूमिहीन मजदूर थे या कारखाने के मजदूर थे वे उपीडडित थे और जिनके पास उत्पादन के साधन थे, वे उपीडडनकारी थे। दूसरे विश्व युद्ध के बाद मार्क्सवादी विचारकों ने एक संशोधन दिया जो एक प्रकार का सांस्कृतिक मार्क्सवाद था, जो आर्थिक स्तर पर नहीं बल्कि सांस्कृतिक स्तर पर उपीडडित और उपीडडनकारी के बीच भेद के बारे में बात करता था। इस प्रकार मार्क्सवादी विचारक 'अर्थ' से 'संस्कृति' पर चले आये। इसे फ्रैंकफर्ट स्कूल ऑफ मार्क्सिज्म के नाम से जाना जाता है। एक महत्वपूर्ण अकादमिक विद्वान हर्बर्ट मार्कस ह्यूज ने मार्क्सवाद का नया मॉडल विकसित किया।और आर्थिक विषमता की जगह नस्ल-भेद का सिद्धांत दिया। उसमे मार्क्स के सिद्धांत को आर्थिक की जगह नस्ल पर लागू किया। मार्क्सवादी अकादमिक विद्वानों को अमरीका में 'क्रिटिकल लॉ थ्योरी' लाए थे उन्होंने उसे आगे बढ़ाते हुए क्रिटिकल रेस थ्योरी बना दी। मार्क्सवादी विचारकों ने अब लिबरल बन कर 'क्रिटिकल रेस थ्योरी' को 'क्रिटिकल कास्ट थ्योरी' में बदल दिया है, जो कहती है कि 'जाति' 'नस्ल' है, और दलित 'काले' लोग व गैर दलित 'गोरे' लोग हैं। हार्दय पहुंचे कुछ भारतीय दलितों ने भी अपनी एगो-दलित परियोजना को इस नये सिद्धांत में ढालने में सहयोग किया। इस परिपेक्ष्य में भी जाति जनगणना की मांग की राजनीति को देखा और समझा जा सकता है।

—अतिथि संपादक,
राजेन्द्र बोड़ा
(वरिष्ठ पत्रकार एवं विश्लेषक)



रामनिवास बैरवा

बड़े और महत्वपूर्ण दो व्यक्तियों की गुप्त या प्रायोजित मीटिंगों का विवरण नहीं मिलता, लेकिन ऐसी मुलाकातों के बाद के घटनाक्रम और परिणाम यह बता देते हैं कि उस मीटिंग में क्या हुआ होगा। पिछले वर्ष (2024 में) केरल में हुई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कार्यकारिणी की बैठक में यह तय किया गया था कि भारत में जातीय जनगणना की जाये। उसी क्रम में 29 अप्रैल, 2025 को आर.एस.एस. के सरसंघ चालक मोहन भागवत ने 7 लोक कल्याण मार्ग पर स्थित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके सरकारी आवास में मुलाकात की थी। अनुमान तो यह लगाया जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी का नया अध्यक्ष चुने जाने के संबंध में मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी के बीच चल रही खींचतान का कोई समाधान निकला गया होगा। लेकिन, 30 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रीमंडल की राजनीतिक समिति की बैठक में निर्णय लिया गया कि आगामी जनगणना के साथ जातिगत जनगणना भी करवाई जायेगी। हालाँकि, भारतीय जनतापार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार विपक्षी पार्टियों की जातीय गणना की मांग का निरन्तर विरोध करती रही है क्योंकि इससे हिंदू-मुस्लिमों को बांटने का उनका एजेंडा कमजोर होता है। लतात है भाजपा अध्यक्ष के चुनाव के मामले में कोई लेन-देन हुआ है।

जातिगत जनगणना की मांग विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के द्वारा अपने-अपने उद्देश्यों को लेकर काफी समय से की जा रही है। उनकी यह मांग जातियों के उन्मूलन या जातियों के

एकीकरण या जातियों सामाजिक उत्थान के लिए नहीं है बल्कि भारतीय समाज के जाति आधारित समाज के विभाजन को संवैधानिक स्थायित्व देने के लिए, उनको यथास्थिति में रखने के लिए की जा रही है। भारतीय जाति आधारित समाज के विभाजन को स्थायित्व देने का कार्य महात्मा गांधी ने भी 1930-32 के दौरान किया था। डॉ. भीमराव अम्बेडकर सभी पिछड़ों और अछूतों के सामाजिक उत्थान के लिए 'दलित' शब्द का इस्तेमाल करते थे ताकि दलितों को जातियों में उप-विभाजन को रोका जा सके।

भारत में संविधान के अंतर्गत लोकतांत्रिक व्यवस्था है जिसमें आम चुनाव के माध्यम से सरकार चलाने वालों को चुना जाता है। प्रत्येक नागरिक को वोट देने का अधिकार है। लेकिन, दलित-वर्गों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों को अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार नहीं है, वे केवल विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के द्वारा मनोनीत व्यक्तियों को ही वोट देकर चुन सकते हैं। भारतीय राजनीति में कांग्रेस पार्टी का एकाधिकार खतम होने पर, 1977 के चुनावों के बाद जब कांग्रेस पार्टी के अलावा अन्य पार्टियां भी सत्ता का स्वाद चख चुकी तो अपने अपने आपको सत्ता के केंद्र में बनाये रखने के लिए अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के वोटों को अपने पक्ष में लेने की मुहिम चली। जिससे परम्परागत चुनाव जीतने वालों के मुकाबले नये लोगों को भी चुना जा सकें। तब 1990 में विश्वनाथ प्रसाद सिंह ने 'अन्य पिछड़ा वर्ग' को आरक्षण देने का संवैधानिक प्रावधान किया जो कि केवल सरकारी नौकरियों से संबंधित था। चुनावों के लिए अन्य पिछड़ा वर्गों (ओ.बी.सी.) को आम चुनावों में आरक्षण नहीं दिया गया लेकिन परम्परागत प्रभुत्वशाली लोगों का वर्चस्व टूटने पर ओबीसी के सम्पन्न लोग अपनी-अपनी पार्टियां बनाकर राज्यों में चुनाव जीतने लगे और सरकारें बनाने लगे।

जातियों की एकता- यह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का शताब्दी वर्ष है। उसकी स्थापना के पहले का भी 50-60 वर्ष का इतिहास है जो आर.एस.एस. को विरासत में मिला था। समाज में जातियों को अस्तित्व हजारों सालों से चला आने के कारण इसे सामान्य, अपरिवर्तनीय माना जाता था। जहां एक तरफ ज्योतिराव फुले, उनकी पत्नी सावित्री बाई फुले तथा उनकी सहयोगिनी फातिमा शेख सामाजिक चेतना जगाने के लिए भी अछूत बालिकाओं को शिक्षित करने का अलख जगा रहे थे, वहीं ब्राह्मण 1857 विद्रोह की असफलता के बाद बालगंगाधर तिलक "स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार" के नारे के साथ पुरानी सनातनी जाति व्यवस्था में किसी भी सुधार का विरोध करते थे। तब से जातियों और धर्म को अलग-अलग करके देखा शुरु किया गया था। मुसलमानों के विरुद्ध सभी जातियों का सामूहिक इस्तेमाल करके उन्हीं बाल गंगाधर तिलक के मुस्लिम विरोधी विचारधारा को बढ़ाने के लिए शिवाजी के नाम का इस्तेमाल किया।

वहीं डॉ. अम्बेडकर दलित-अछूत जातियों का शिक्षा दिलाकर सरकार के समर्थन से सरकारी नौकरियों के लिए रास्ता बना रहे थे। लेकिन, इनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं होने के कारण सरकार के समर्थन की आशा करते थे। इनके विपरीत, गांधी जी पर्याप्त राजनीतिक पृष्ठभूमि होने और भारतीय समाज की आध्यात्मिक सुरुचियों-कुरीतियों को बनाये रखने के लिए स्वयं संत महात्मा के रूप में अवतरित हुए और अपना राजनीतिक उत्तराधिकार जवाहरलाल नेहरू ने दे दिया। इस प्रकार कांग्रेस समाज के जातीय विभाजन को यथास्थिति में रखने के प्रयास किये।

भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में सरकार बना लेने के बाद पूंजीपति-व्यापारी वर्ग का एकाधिकार जैसा हो जाने के कारण अन्य विरोधी राजनीतिक पार्टियों का सत्ता प्राप्ति का संघर्ष रूक सा गया है। भारतीय जनता पार्टी और आर.एस.एस. की सत्ता में बने रहने के लिए तथा विभिन्न जातियों को अपना समर्थक बनाये रखने के लिए उन्हें सामूहिक रूप से मुसलमानों के खिलाफ लामबद्ध करते हैं। मुस्लिम विरोध के हालात में यह हमारे लिए चिन्तन एवं चिंता का महत्वपूर्ण विषय होना चाहिये।

जहां रोजगार की गारंटी है (IIT, AIMS, IIM आदि) ऐसे श्रेष्ठ शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश प्राप्त करने हेतु तथा सरकारी नौकरी के लिए कॉलेज के स्थान पर कोचिंग संस्थान युवाओं के आकर्षण का केंद्र बन गए हैं। सरकारी नौकरी के लिए जो व्यवस्था बनाई है उसमें चयन के लिए युवकों को अपने परंपरागत कॉलेज के स्थान पर कोचिंग संस्थानों का अध्ययन-अध्यापन ज्यादा प्रभावी दिखाई दे रहा है। कोचिंग संस्थानों में प्रतियोगी परीक्षाओं के पाठ्यक्रम के अनुरूप ही पढ़ने-लिखने की व्यवस्था कर रखी है। कोचिंग में केवल और केवल क्लास रूम टीचिंग ही है।

राजकीय अवकाशों की लम्बी श्रृंखला, छात्रसंघ चुनाव, नारेबाजी, हड़ताल जैसी गतिविधियों के लिए कोचिंग संस्थानों में कोच स्थान नहीं है। इन अनुवादक कार्यों में छात्रों को समय खराब नहीं करना पड़ता है। विद्यार्थियों की मानसिकता में एक अच्छा परिवर्तन यह आया है कि वे आज के प्रतियोगी माहौल में समय के

आर.एस.एस. को विरासत में मिला था। समाज में जातियों को अस्तित्व हजारों सालों से चला आने के कारण इसे सामान्य, अपरिवर्तनीय माना जाता था। जहां एक तरफ ज्योतिराव फुले, उनकी पत्नी सावित्री बाई फुले तथा उनकी सहयोगिनी फातिमा शेख सामाजिक चेतना जगाने के लिए भी अछूत बालिकाओं को शिक्षित करने का अलख जगा रहे थे, वहीं ब्राह्मण 1857 विद्रोह की असफलता के बाद बालगंगाधर तिलक "स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार" के नारे के साथ पुरानी सनातनी जाति व्यवस्था में किसी भी सुधार का विरोध करते थे। तब से जातियों और धर्म को अलग-अलग करके देखा शुरु किया गया था। मुसलमानों के विरुद्ध सभी जातियों का सामूहिक इस्तेमाल करके उन्हीं बाल गंगाधर तिलक के मुस्लिम विरोधी विचारधारा को बढ़ाने के लिए शिवाजी के नाम का इस्तेमाल किया।

वहीं डॉ. अम्बेडकर दलित-अछूत जातियों का शिक्षा दिलाकर सरकार के समर्थन से सरकारी नौकरियों के लिए रास्ता बना रहे थे। लेकिन, इनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं होने के कारण सरकार के समर्थन की आशा करते थे। इनके विपरीत, गांधी जी पर्याप्त राजनीतिक पृष्ठभूमि होने और भारतीय समाज की आध्यात्मिक सुरुचियों-कुरीतियों को बनाये रखने के लिए स्वयं संत महात्मा के रूप में अवतरित हुए और अपना राजनीतिक उत्तराधिकार जवाहरलाल नेहरू ने दे दिया। इस प्रकार कांग्रेस समाज के जातीय विभाजन को यथास्थिति में रखने के प्रयास किये।

भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में सरकार बना लेने के बाद पूंजीपति-

व्यापारी वर्ग का एकाधिकार जैसा हो जाने के कारण अन्य विरोधी राजनीतिक पार्टियों का सत्ता प्राप्ति का संघर्ष रूक सा गया है। भारतीय जनता पार्टी और आर.एस.एस. की सत्ता में बने रहने के लिए तथा विभिन्न जातियों को अपना समर्थक बनाये रखने के लिए उन्हें सामूहिक रूप से मुसलमानों के खिलाफ लामबद्ध करते हैं। मुस्लिम विरोध के हालात में यह हमारे लिए चिन्तन एवं चिंता का महत्वपूर्ण विषय होना चाहिये।

जहां रोजगार की गारंटी है (IIT, AIMS, IIM आदि) ऐसे श्रेष्ठ शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश प्राप्त करने हेतु तथा सरकारी नौकरी के लिए कॉलेज के स्थान पर कोचिंग संस्थान युवाओं के आकर्षण का केंद्र बन गए हैं। सरकारी नौकरी के लिए जो व्यवस्था बनाई है उसमें चयन के लिए युवकों को अपने परंपरागत कॉलेज के स्थान पर कोचिंग संस्थानों का अध्ययन-अध्यापन ज्यादा प्रभावी दिखाई दे रहा है। कोचिंग संस्थानों में प्रतियोगी परीक्षाओं के पाठ्यक्रम के अनुरूप ही पढ़ने-लिखने की व्यवस्था कर रखी है। कोचिंग में केवल और केवल क्लास रूम टीचिंग ही है।

राजकीय अवकाशों की लम्बी श्रृंखला, छात्रसंघ चुनाव, नारेबाजी, हड़ताल जैसी गतिविधियों के लिए कोचिंग संस्थानों में कोच स्थान नहीं है। इन अनुवादक कार्यों में छात्रों को समय खराब नहीं करना पड़ता है। विद्यार्थियों की मानसिकता में एक अच्छा परिवर्तन यह आया है कि वे आज के प्रतियोगी माहौल में समय के

आर.एस.एस. को विरासत में मिला था। समाज में जातियों को अस्तित्व हजारों सालों से चला आने के कारण इसे सामान्य, अपरिवर्तनीय माना जाता था। जहां एक तरफ ज्योतिराव फुले, उनकी पत्नी सावित्री बाई फुले तथा उनकी सहयोगिनी फातिमा शेख सामाजिक चेतना जगाने के लिए भी अछूत बालिकाओं को शिक्षित करने का अलख जगा रहे थे, वहीं ब्राह्मण 1857 विद्रोह की असफलता के बाद बालगंगाधर तिलक "स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार" के नारे के साथ पुरानी सनातनी जाति व्यवस्था में किसी भी सुधार का विरोध करते थे। तब से जातियों और धर्म को अलग-अलग करके देखा शुरु किया गया था। मुसलमानों के विरुद्ध सभी जातियों का सामूहिक इस्तेमाल करके उन्हीं बाल गंगाधर तिलक के मुस्लिम विरोधी विचारधारा को बढ़ाने के लिए शिवाजी के नाम का इस्तेमाल किया।

वहीं डॉ. अम्बेडकर दलित-अछूत जातियों का शिक्षा दिलाकर सरकार के समर्थन से सरकारी नौकरियों के लिए रास्ता बना रहे थे। लेकिन, इनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं होने के कारण सरकार के समर्थन की आशा करते थे। इनके विपरीत, गांधी जी पर्याप्त राजनीतिक पृष्ठभूमि होने और भारतीय समाज की आध्यात्मिक सुरुचियों-कुरीतियों को बनाये रखने के लिए स्वयं संत महात्मा के रूप में अवतरित हुए और अपना राजनीतिक उत्तराधिकार जवाहरलाल नेहरू ने दे दिया। इस प्रकार कांग्रेस समाज के जातीय विभाजन को यथास्थिति में रखने के प्रयास किये।

भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में सरकार बना लेने के बाद पूंजीपति-

व्यापारी वर्ग का एकाधिकार जैसा हो जाने के कारण अन्य विरोधी राजनीतिक पार्टियों का सत्ता प्राप्ति का संघर्ष रूक सा गया है। भारतीय जनता पार्टी और आर.एस.एस. की सत्ता में बने रहने के लिए तथा विभिन्न जातियों को अपना समर्थक बनाये रखने के लिए उन्हें सामूहिक रूप से मुसलमानों के खिलाफ लामबद्ध करते हैं। मुस्लिम विरोध के हालात में यह हमारे लिए चिन्तन एवं चिंता का महत्वपूर्ण विषय होना चाहिये।

जहां रोजगार की गारंटी है (IIT, AIMS, IIM आदि) ऐसे श्रेष्ठ शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश प्राप्त करने हेतु तथा सरकारी नौकरी के लिए कॉलेज के स्थान पर कोचिंग संस्थान युवाओं के आकर्षण का केंद्र बन गए हैं। सरकारी नौकरी के लिए जो व्यवस्था बनाई है उसमें चयन के लिए युवकों को अपने परंपरागत कॉलेज के स्थान पर कोचिंग संस्थानों का अध्ययन-अध्यापन ज्यादा प्रभावी दिखाई दे रहा है। कोचिंग संस्थानों में प्रतियोगी परीक्षाओं के पाठ्यक्रम के अनुरूप ही पढ़ने-लिखने की व्यवस्था कर रखी है। कोचिंग में केवल और केवल क्लास रूम टीचिंग ही है।

राजकीय अवकाशों की लम्बी श्रृंखला, छात्रसंघ चुनाव, नारेबाजी, हड़ताल जैसी गतिविधियों के लिए कोचिंग संस्थानों में कोच स्थान नहीं है। इन अनुवादक कार्यों में छात्रों को समय खराब नहीं करना पड़ता है। विद्यार्थियों की मानसिकता में एक अच्छा परिवर्तन यह आया है कि वे आज के प्रतियोगी माहौल में समय के

राजकीय अवकाशों की लम्बी श्रृंखला, छात्रसंघ चुनाव, नारेबाजी, हड़ताल जैसी गतिविधियों के लिए कोचिंग संस्थानों में कोच स्थान नहीं है। इन अनुवादक कार्यों में छात्रों को समय खराब नहीं करना पड़ता है। विद्यार्थियों की मानसिकता में एक अच्छा परिवर्तन यह आया है कि वे आज के प्रतियोगी माहौल में समय के

राजकीय अवकाशों की लम्बी श्रृंखला, छात्रसंघ चुनाव, नारेबाजी, हड़ताल जैसी गतिविधियों के लिए कोचिंग संस्थानों में कोच स्थान नहीं है। इन अनुवादक कार्यों में छात्रों को समय खराब नहीं करना पड़ता है। विद्यार्थियों की मानसिकता में एक अच्छा परिवर्तन यह आया है कि वे आज के प्रतियोगी माहौल में समय के

राजकीय अवकाशों की लम्बी श्रृंखला, छात्रसंघ चुनाव, नारेबाजी, हड़ताल जैसी गतिविधियों के लिए कोचिंग संस्थानों में कोच स्थान नहीं है। इन अनुवादक कार्यों में छात्रों को समय खराब नहीं करना पड़ता है। विद्यार्थियों की मानसिकता में एक अच्छा परिवर्तन यह आया है कि वे आज के प्रतियोगी माहौल में समय के

राजकीय अवकाशों की लम्बी श्रृंखला, छात्रसंघ चुनाव, नारेबाजी, हड़ताल जैसी गतिविधियों के लिए कोचिंग संस्थानों में कोच स्थान नहीं है। इन अनुवादक कार्यों में छात्रों को समय खराब नहीं करना पड़ता है। विद्यार्थियों की मानसिकता में एक अच्छा परिवर्तन यह आया है कि वे आज के प्रतियोगी माहौल में समय के

राजकीय अवकाशों की लम्बी श्रृंखला, छात्रसंघ चुनाव, नारेबाजी, हड़ताल जैसी गतिविधियों के लिए कोचिंग संस्थानों में कोच स्थान नहीं है। इन अनुवादक कार्यों में छात्रों को समय खराब नहीं करना पड़ता है। विद्यार्थियों की मानसिकता में एक अच्छा परिवर्तन यह आया है कि वे आज के प्रतियोगी माहौल में समय के

मिलते रहने की सम्भावना बनी रहेगी। शायद इन्हीं वैचारिक तर्कों के आधार पर आर.एस.एस. ने अपनी केरल की बैठक में जातिगत जनगणना का निर्णय लिया और नरेंद्र मोदी सरकार को मोहन भागवत ने नैतिकत्वक सलाह दी कि जातिगत जनगणना करवा ली जाये।

इसका कार्यपालिका के अधिकार का एक अन्य पहलू भी है। यह तो सबके सामने है कि 2021 में की जाने वाली जनगणना को जहां 5-6 साल तक स्थगित रखा गया है तथा इसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है। दूसरा यह है कि 2011 की जनगणना के आंशिक आंकड़े ही अभी तक जारी किये गये तो इस बात की क्या गारंटी है कि 2026 में आगामी जनगणना जो कि जातिगत आधार पर करने की कही जा रही है, पूरी कर ही ली जायेगी। और अगर जनगणना पूरी कर भी ली गई तो उसके आंकड़े तत्काल जारी कर ही दिये जायेंगे? घोषणाएं एक बात हैं और उन्हें अमल में लाना दूसरी बात है। फिर इस जनगणना से जुड़े और भी संवैधानिक प्रावधान हैं जिनमें लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं को सदस्य संख्या और निर्वाचन क्षेत्रों का पुनः निर्धारण।

जातिगत जनगणना के बाद केवल धार्मिक आधार पर ही एकीकरण या ध्रुवीकरण क्यों आवश्यक है, क्या किसी और दूसरे रास्ते जातियों का एकताबद्ध होना संभव नहीं है? ऐसा संभव है, बस विचार लोक से हट कर करना होगा। जब किसान पूरे देश में किसान ही है तो फिर उन्हें किसान ही बने रहने देना होगा, क्यों उन्हें धर्म के आधार पर एकताबद्ध करने के लिए मजबूर किया जाये। इसी तरह से मजदूर पूरे देश में सिर्फ मजदूर ही है चाहे वे हिंदू हों, चाहे वे मुसलमान हों, चाहे वे ईसाई हों, उन्हें सिर्फ मजदूरों के रूप में ही एकताबद्ध क्यों ना किया जाये? यह उनका अंतर्राष्ट्रीय पहचान भी है, धर्म उनकी अंतर्राष्ट्रीय पहचान कभी नहीं हो सकती। सच है सत्ताधारी पार्टियों का अन्तीविरोध भारत की जनता के लिए राजनीतिक प्रशिक्षण के नये-नये द्वार खोलते रहेंगे।

—रामनिवास बैरवा
पूर्व क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

कॉलेज बनाम कोचिंग

के हालात में यह हमारे लिए चिन्तन एवं चिंता का महत्वपूर्ण विषय होना चाहिये।

जहां रोजगार की गारंटी है (IIT, AIMS, IIM आदि) ऐसे श्रेष्ठ शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश प्राप्त करने हेतु तथा सरकारी नौकरी के लिए कॉलेज के स्थान पर कोचिंग संस्थान युवाओं के आकर्षण का केंद्र बन गए हैं। सरकारी नौकरी के लिए जो व्यवस्था बनाई है उसमें चयन के लिए युवकों को अपने परंपरागत कॉलेज के स्थान पर कोचिंग संस्थानों का अध्ययन-अध्यापन ज्यादा प्रभावी दिखाई दे रहा है। कोचिंग संस्थानों में प्रतियोगी परीक्षाओं के पाठ्यक्रम के अनुरूप ही पढ़ने-लिखने की व्यवस्था कर रखी है। कोचिंग में केवल और केवल क्लास रूम टीचिंग ही है।

राजकीय अवकाशों की लम्बी श्रृंखला, छात्रसंघ चुनाव, नारेबाजी, हड़ताल जैसी गतिविधियों के लिए कोचिंग संस्थानों में कोच स्थान नहीं है। इन अनुवादक कार्यों में छात्रों को समय खराब नहीं करना पड़ता है। विद्यार्थियों की मानसिकता में एक अच्छा परिवर्तन यह आया है कि वे आज के प्रतियोगी माहौल में समय के

उपयोग के प्रति बहुत गंभीर है। दूसरी और विश्वविद्यालय पाठ्यक्रमों की रचना का उद्देश्य ही भिन्न है। कॉलेज एवं विश्वविद्यालय में संचालन पर सरकार जहाँ करोड़ों रुपए खर्च कर रही है वहीं दूसरी ओर क्लास रूम खाली पड़े हैं। न्यायालय द्वारा निर्धारित 75% उपस्थिति का मजाक हो रहा है। शिक्षक, विद्यार्थी, माता-पिता, समाज सभी इस अव्यवस्था के साक्षी होने के बावजूद शान्त हैं परन्तु आखिर कब तक.....!

एक तरफ आलीशान भवन, फर्नीचर, प्रयोगशाला, पुस्तकालय एवं यू.जी.सी. द्वारा निर्धारित योग्यताधारी अध्यापक होने के बावजूद प्रातः 10:00 बजे जैसे अनुकूल समय पर भी विद्यार्थी क्लास रूम से दूर भाग रहा है और कोचिंग सेंटर में 10 बघा फीस देकर बेसमेंट में लगेंगे वंचा पर बैठकर प्रातः 6:00 बजे सामान्य काउंसलर से बड़ी गंभीरता के साथ अध्ययनरत हैं। आज अभिभावक भी बच्चे को टचयुशन पर भेजकर गर्व का अनुभव करने लग गये हैं। ऐसी स्थिति में कोचिंग सेंटरस की आलोचना करने से काम नहीं चलेगा अपितु शोध की आवश्यकता यह है कि ऐसा क्यों हो

रहा है, और उसे ठीक करने के लिये हमारी वर्तमान व्यवस्था में किस प्रकार के परिवर्तन अपेक्षित हैं? न केवल भारत अपितु पृथिवी के कई देशों में टचयुशन का बाजार तेजी से बढ़ रहा है। औपचारिक शिक्षा का सिस्टम कमजोर होने से कोचिंग को बढ़ावा मिला है। एक जानकारी के अनुसार भारत, पाकिस्तान से लेकर इंडोनेशिया तक करीब 25 करोड़ बच्चे टचयुशन ले रहे हैं। हांगकांग में 72%, दक्षिण कोरिया में 79%, जापान में 52% छात्र टचयुशन पढ़ते हैं। चीन में 2021 में पाबंदी से पहले 38% छात्र टचयुशन पढ़ते थे। हमारे देश में कोटा शहर कोचिंग की राष्ट्रीय राजधानी बन चुका है। जहाँ प्रतिवर्ष पूरे देश से लगभग दो लाख विद्यार्थी कोचिंग संस्थानों में अध्ययन करने आते हैं।

इस संक्षिप्त आलेख के माध्यम से मेरा सुझाव है कि सरकारी नौकरी में चयन हेतु आयोजित प्रतियोगी परीक्षा के प्राप्तांकों की राष्ट्रीय राजधानी व स्नातकोत्तर परीक्षाओं में प्राप्त अंकों का 20 फीसदी से 30 फीसदी वजन रखा जाना चाहिये। निःसन्देह गणना कठिन है क्योंकि राज्यों की परीक्षा व्यवस्था में भिन्नताएं बहुत हैं। दूसरा,

विश्वविद्यालय पाठ्यक्रमों को आधार मान कर ही प्रतियोगी परीक्षाओं का पाठ्यक्रम बनाया जाना चाहिये। इससे कॉलेजों में स्वाभाविक रूप से उपस्थिति बढ़ेगी।

धरातल की सच्चाई को समझते हुए, कोचिंग संस्थानों की उपस्थिति को सहर्ष स्वीकार करते हुए सरकार को कॉलेजों की भांति कोचिंग संस्थानों को संचालित करने के लिये शिक्षकों, भवन, फर्नीचर, पुस्तकालय, आदि के लिए निवेश बनाने हुए लागू करना होगा, जिससे छात्रों को कॉलेजों की भांति कोचिंग सेंटर पर भी आवश्यक सुविधाएं मिलने लगेंगी। नालंदा और तक्षशिला के समय से इतिहास गवाह है कि हमें विश्वविद्यालयों की समाज में उपयोगिता बनाये रखनी है। हालात इतने खराब नहीं हैं इसलिए इन्हें पुनः जीवन्त किया जा सकता है और यथाशीघ्र किया जाना चाहिये। इस विषय पर विद्वान शिक्षकों एवं विद्यार्थियों के मध्य चर्चा - परिचर्चा आवश्यक है।

—डॉ. कैलाश सोडाणी,
कुलगुरु,
वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

विवाह सम्मेलन में 85 जोड़े 10, डाउनिंग स्ट्रीट से 7, लोक कल्याण मार्ग तक

परिणय सूत्र में बंधे

सरवाड़, (निर्स)। सरवाड़ शहर में यदुवंशी सैनी समाज का नवम सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन समिति के तत्वावधान में मंगलवार को शहर स्थित यदुवंशी माली भवन में किया गया।

सम्मेलन में समाज के 85 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। वहीं बारात के माली भवन पहुंचने पर तोरण व

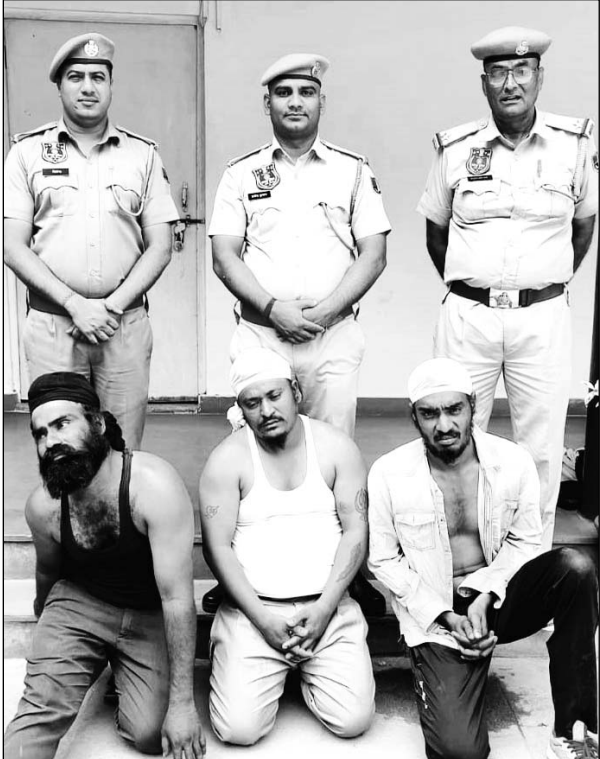
वरमाला की रस्म निभाई गई। बाद में पंडितों द्वारा 85 जोड़ों का पाणिग्रहण संस्कार करवाकर परिणय सूत्र में बांधा।

गुजरात की ताला-चाबी गैंग के तीन शातिर बदमाश गिरफ्तार

जयपुर। मुरलीपुरा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ताला-चाबी ठीक करने के बहाने घर में घुस कर चोरी करने वाली गुजरात की ताता-चाबी गैंग के तीन शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास

- **चाबी बनाने के बहाने अलमारी से चुराते थे नकदी और जेवरात**
- **पुलिस ने जब्त किया चुराए गए सामान**
- **पुलिस पूछताछ में और भी कई वारदातें खुलने की आशंका**

से चुराया गया सोने-चांदी के जेवराल सहित नकदी बरामद की है। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस उपायुक्त जयपुर (पश्चिम) अमित कुमार ने बताया कि मुरलीपुरा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ताला-चाबी ठीक करने के बहाने घर में घुस कर चोरी करने वाली गुजरात की ताता-चाबी गैंग के शातिर बदमाश सरदार सतनाम सिंह (29) निवासी दाहोद गुजरात, सजो सिंह उर्फ सरदार सजो देवल (30) निवासी दाहोद गुजरात और सरदार राजेन्द्र सिंह (35) निवासी कोतावाली डूंगरपुर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों से चोरी



मुरलीपुरा थाना पुलिस ने ताला-चाबी ठीक करने के बहाने घर में घुस कर चोरी करने वाली गुजरात की ताता-चाबी गैंग के तीन शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है।

का माल एक आर्टिफिशियल चैन, एक आभूषण एवं आधार कार्ड-की बरामद आर्टिफिशियल मंगलसूत्र, अन्य किया गया है। पुलिस पूछताछ में और

भी कई वारदातें खुलने की आशंका जताई जा रही है।

थानाधिकारी वीरेंद्र कुरील ने बताया कि वारदात करने के लिए गुजरात से आकर होटल में ठहरते थे और गैंग के सदस्य कॉलोनियों में पैदल घूमते हुए ताले-चाबी ठीक करने का बहाना कर वारदात करते थे। घर में अकेली महिला या सुनसान मकान देखकर दो सदस्य घर के अंदर जाते हैं और एक बाहर निगरानी रखता है। अंदर जाकर अलमारी का ताला ठीक करने के बहाने घरवालों का ध्यान भटकाते हैं और मौका देखकर कीमती सामान चुराकर फरार हो जाते हैं। सीसीटीवी से हुई पहचान पुलिस ने बताया कि आरोपियों को पकड़ने के लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया था। टीम ने 100 से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगाली। आरोपियों की गतिविधियां कैमरों में कैद हुईं जिन्हें देस कर पुलिस ने उन्हें दादी का फाटक क्षेत्र से गिरफ्तार किया।

पुलिस उनसे अन्य वारदातों के संबंध में पूछताछ कर रही है, जिससे कई और चोरी की वारदातों का खुलासा होने की संभावना है।

पुलिस ने आमजन से अपील की है कि अज्ञात व्यक्तियों को घर में प्रवेश न दें और ताला-चाबी बनाने वाले फेरीवालों से सतर्क रहें। किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना नजदीकी थाने को दें।

लू-तापघात प्रबंधन के लिए हर जिले में होगा सघन निरीक्षण

जयपुर। राज्य में लू-तापघात की स्थितियों के दृष्टिगत दवाओं की निर्बांध एवं समुचित आपूर्ति तथा चिकित्सा उपकरणों की क्रियाशीलता को लेकर राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन की ओर से ग्रीष्मकालीन सघन निरीक्षण अभियान चलाया जाएगा। अभियान के लिए 27 टीमों का गठन किया गया है।

उल्लेखनीय है कि विगत दिनों मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश में लू-तापघात की स्थितियों में आमजन के स्वास्थ्य को लेकर पुख्ता प्रबंध सुनिश्चित करने के निर्देश दिए थे। इन निर्देशों की अनुपालना में चिकित्सा मंत्री गजेन्द्र सिंह खीवसर के मार्गदर्शन में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से लू-तापघात से बचाव एवं उपचार आदि के संबंध में जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं।

आरएमएससीएल की प्रबंध निदेशक नेहा गिरि ने बताया कि राज्य में होटवेव की सम्भावनाओं को देखते हुए ग्रीष्मकालीन सघन निरीक्षण अभियान चलाया जाएगा। निगम में कार्यरत विशेषाधिकारी, समस्त कार्यकारी निदेशक, लेखाधिकारी तथा जिला औषधि भण्डार गृह के प्रभारी अधिकारी को जिलों का आवंटन कर यह निरीक्षण करवाए जाएगा। इसके लिए दो सदस्यीय 27 टीमों का गठन किया गया है। यह टीमें निरीक्षण कर जिले में औषधियों, उपकरणों की उपलब्धता एवं क्रियाशीलता को लेकर 30 मई तक अपनी विस्तृत रिपोर्ट देंगी।

सामूहिक पंजीकरण शिविर में श्रमिकों को जारी हुए ई-श्रम



जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर महानगर-प्रथम व द्वितीय के संयुक्त तत्वावधान में मंगलवार को हीरापुरा चौराहा 200 फीट बाईपास स्थित मजदूर चौखटी पर सामूहिक पंजीकरण शिविर का आयोजन किया गया।

जयपुर। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर जिला, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर महानगर-प्रथम व द्वितीय के संयुक्त तत्वावधान में मंगलवार को हीरापुरा चौराहा 200 फीट बाईपास स्थित मजदूर चौखटी पर सामूहिक पंजीकरण शिविर का आयोजन किया गया। श्रम विभाग, कॉमन सर्विस सेंटर, ट्रेड यूनियन, एक्शन एड तथा आजीविका एनजीओ के सहयोग एवं समन्वय से आयोजित शिविर में 63 श्रमिकों का मौके पर ही ऑनलाईन ई-श्रम कार्ड जारी किया गया, साथ ही 65 श्रमिक कार्ड फार्म भरवाए गए एवं 200 से अधिक श्रमिक हाजिरी डायरी वितरित की गई।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर जिला के सचिव पवन कुमार जैनवाल तथा दीपेन्द्र माथुर सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर महानगर प्रथम ने चौखटी पर उपस्थित

श्रमिकों को उनके विधिक अधिकारों, श्रम विभाग की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान की।

जैनवाल ने यह भी बताया कि जो श्रमिक शिविर में ऑनलाईन पंजीकरण से वंचित रह जाएंगे, उनके लिए बुधवार को विश्वकर्मा रोड नम्बर 14 सीकर रोड स्थित मजदूर चौखटी तथा 8 मई को इंडिया गेट सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया स्थित मजदूर चौखटी पर भी ऑनलाईन पंजीकरण शिविर का आयोजन किया जाएगा। पंजीकरण हेतु श्रमिकों को आधार कार्ड, बैंक पासबुक तथा मोबाइल साध लेकर मौके पर आना होगा। शिविर में श्रमिकों को श्रम विभाग की विभिन्न योजनाओं जैसे निर्माण श्रमिक शिक्षा एवं कौशल विकास योजना, निर्माण श्रमिक जीवन व भविष्य सुरक्षा योजना, सिलिकोसिस पीडित हिताधिकारियों हेतु सहायता योजना, हिताधिकारी की सामान्य अथवा दुर्घटना में मृत्यु या घायल होने की दशा में सहायता योजना, प्रसूति

सहायता योजना, शुभशक्ति योजना, निर्माण श्रमिक सुलभ्य आवास योजना, निर्माण श्रमिक ओजार /टूलकिट सहायता योजना, निर्माण श्रमिक एवं उनके आश्रित बच्चों द्वारा भारतीय/राजस्थान प्रशासनिक सेवा हेतु आयोजित प्रारम्भिक प्रतियोगी परीक्षा उत्तीर्ण करने पर प्रोत्साहन योजना एवं अन्य योजनाओं की विस्तृत जानकारी प्रदान की जाएगी।

शिविर के दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर जिला से पीएलवी श्री सुरेश कुमार गुर्जर ने श्रमिकों का ऑनलाईन पंजीकरण करने में सहायता प्रदान की। शिविर के दौरान पल्लवी शर्मा सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर महानगर-द्वितीय, श्रम विभाग से भारती पिन्डा, अनुपम गौतम, सीएससी से सुरेंद्र कुमार जांगिड तथा दीपक जांगिड, ट्रेड यूनियन से अनिल बैरवा तथा तुषार बैरवा, एक्शन एड एनजीओ से मूलचंद शर्मा तथा हेमलता व अन्य उपस्थित रहे।

कुसुम योजना में एक हजार मेगावाट ऊर्जा उत्पादन क्षमता का नया कीर्तिमान बनाया

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में सौर ऊर्जा का सूर्य निश्चित तौर पर देश के पश्चिमी राज्य राजस्थान में चमक रहा है। सूर्य भगवान की विशेष कृपा से प्रदेश की सुनहरी रेतौली घरती में सौर ऊर्जा उत्पादन की अपार संभावनाएँ हैं, जिनके दोहन के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहले दिन से ही निरंतर प्रयासरत हैं।

राजस्थान को ऊर्जा आत्मनिर्भर बनाने के लक्ष्य की दिशा में पीएम-कुसुम योजना के माध्यम से एक बड़ी कामयाबी मिली है तथा राजस्थान ऐसा अग्रणी राज्य बन गया है जहां इस योजना के कम्पोनेंट-ए एवं कम्पोनेंट-सी के अन्तर्गत सौर ऊर्जा उत्पादन 1 हजार मेगावाट से अधिक हो गया है। सौर ऊर्जा का उपयोग कर किसानों को दिन में बिजली आपूर्ति की दिशा में भी राजस्थान तेजी से आगे बढ़ रहा है जिससे आज प्रदेश में 1 लाख 70 हजार से अधिक किसानों को दिन में बिजली सुलभ होने लगी है। पीएम कुसुम योजना के कम्पोनेंट-ए एवं कम्पोनेंट-सी के तहत ही 560 ग्रिड कनेक्टेड विफेन्द्रित सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित कर 70 हजार से अधिक कृषि उपभोक्ताओं को दिन में बिजली दी जा रही है। वहीं इस योजना के कम्पोनेंट-बी में लगभग 1 लाख किसानों के कृषि पम्पों को सौर ऊर्जा से जोड़ा जा चुका है। राज्य द्वारा

- **मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में सौर ऊर्जा क्रांति का साक्षी बनता राजस्थान**
- **1 लाख 70 हजार से अधिक किसानों को दिन में मिलने लगी बिजली**

योजना के सफल क्रियान्वयन को देखते हुए भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान कुसुम-ए में दो बार में कुल 6 हजार मेगावाट क्षमता के संयंत्रों के अतिरिक्त आवंटन को स्वीकृति दी है तथा कम्पोनेंट-सी में 2 लाख सोलर पम्पों का अतिरिक्त आवंटन किया है। इस प्रकार इस योजना में प्रदेश में लगभग 12 हजार मेगावाट क्षमता के प्लांट स्थापित किए जाने का लक्ष्य रख कार्य किया जा रहा है।

पूर्ववर्ती सरकार के अंतिम तीन सालों में जहां केवल 92 प्लांट ही स्थापित किए जा सके थे। वहीं आज प्रदेश में कम्पोनेंट-सी में लगभग हर दिन औसतन एक नया सौर ऊर्जा संयंत्र ग्रिड से जुड़ रहा है। बीते 6 माह में प्लांटों के क्रियाशील होने की गति में और तेजी आई है। इस अवधि में कम्पोनेंट-ए में 183 मेगावाट क्षमता के 134 तथा कम्पोनेंट-सी में 514 मेगावाट क्षमता के 196 प्लांट स्थापित हुए हैं। यह प्रगति इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है कि जबसे यह योजना प्रारंभ हुई उसके बाद से ऊर्जा उत्पादन में प्रतिदिन औसतन

चार से पांच मेगावाट क्षमता की अतिरिक्त बढ़ोतरी हो रही है। योजना के तहत यह प्लांट मुख्यतः राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित हो रहे हैं जहां कृषि कनेक्शन अधिक संख्या में हैं। खेत के समीप भूमि पर लग रहे अधिकतम 5 मेगावाट क्षमता तक के इन सौर ऊर्जा संयंत्रों से किसानों को खेती से जुड़े कार्यों के लिए दिन में बिजली सुलभ होने लगी है। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमता के एक नए युग की शुरुआत हुई है। अपनी भूमि पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाकर किसान अन्नदाता के साथ-साथ ऊर्जादाता भी बन रहे हैं जिससे उन्हें आमदनी का एक अतिरिक्त जरिया भी मिला है।

योजना में फीडर लेवल सोलरइजेशन के अन्तर्गत 33/11 केवी ग्रिड सब स्टेशन के लगभग 5 किलोमीटर के दायरे में सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए जाने का प्रावधान है। कंपोनेंट-ए में अधिकतम 2 मेगावाट क्षमता तक तथा कंपोनेंट-सी में अधिकतम 5 मेगावाट क्षमता तक के ग्रिड कनेक्टेड सोलर प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं। कंपोनेंट-सी में सौर

संयंत्र की स्थापना पर भारत सरकार लागत का अधिकतम 30 प्रतिशत (अधिकतम 1 करोड़ 5 लाख रूपए प्रति मेगावाट) तक अनुदान देती है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वर्ष-2027 तक किसानों को कृषि कार्य के लिए दिन में बिजली उपलब्ध कराने का संकल्प व्यक्त किया है। इस संकल्प को साकार करने की दिशा में यह योजना महत्वपूर्ण है। राज्य सरकार द्वारा इसे पल्लेगशिप योजना के रूप में भी सम्मिलित किया गया है।

डिस्कॉम्स द्वारा मानक संचालन प्रक्रिया तैयार कर सौर संयंत्रों की स्थापना में आने वाली बाधाओं को दूर किया गया। अवॉई जारी होने के बाद पावर परसेज एग्रीमेंट को अंतिम रूप देने, सौर संयंत्र को 11 केवी एवं 33 केवी प्रसारण लाइनों के माध्यम से ग्रिड से जोड़ने, ट्रांसफार्मर तथा मीटर से संबंधित स्वीकृतियों के कार्यों, सोलर प्लांट्स के निरीक्षण तथा साइट विजिट्स को विद्युत वितरण निगमों द्वारा निर्धारित समयवधि में पूर्ण किया जा रहा है। साथ ही जिला कलक्टरों को विद्युत लाइन विछाने की राह में आ रही बाधाओं को दूर करने के दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। योजना के फलीभूत होने का फायदा विद्युत वितरण निगमों को लगभग 3 रूपए प्रति यूनिट की सस्ती बिजली की उपलब्धता के रूप में मिल रहा है। स्थानीय स्तर पर पैदा

खानों के माइनिंग प्लान का ऑनलाइन अनुमोदन शुरु : टी.रविकांत

जयपुर। राज्य के खान विभाग ने खानों के माइनिंग प्लान व माइनिंग योजनाओंके ऑनलाईन अनुमोदन की प्रक्रिया शुरु कर दी है। प्रमुख सचिव माइन्स, भूविज्ञान एवं पेट्रोलियम टी. रविकान्त ने बताया कि राज्य सरकार ने माइनिंग सेक्टर में सरलीकरण और पारदर्शी व्यवस्था की दिशा में एक कदम और बढ़ाते हुए पिछले दिनों एक मई से माइनिंग प्लान व माइनिंग योजनाओं का ऑनलाईन अनुमोदन का निर्णय किया था। उन्होंने बताया कि ऑनलाईन अनुमोदन की प्रक्रिया आरंभ हो गई है और जयपुर, ब्यावर, सिरोही, बारां, बांसवाड़ा और चुरु में लाइमस्टोन बर्निंग, मेसेनरी स्टोन, ग्रेनाइट, लाइमस्टोन क्रशर और क्वार्टज फेल्सपार के माइनिंग प्लान व माइनिंग योजनाएं अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की गई हैं।

टी. रविकान्त ने बताया कि नई व्यवस्था से करीब 30 हजार अप्रधान खनिज लीजधारक और क्वारी लाइसेंसधारक लाभान्वित हो सकेंगे। अब उन्हें योजनाओं के अनुमोदन के लिए खनिज विभाग के कार्यालयों में चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। अप्रधान खनिजों के माइनिंग लीजधारकों व क्वारी लाइसेंसधारकों को माइनिंग प्लान व माइनिंग एकीम का अनुमोदन करवाना होता है। नियमानुसार विभाग द्वारा 90 दिवस में अनुमोदन की कार्रवाई पूरी करनी होती है पर अनुमोदन में इससे अधिक समय भी लग जाता है।

दिल्ली-एनसीआर में पटाखे बैन

जयपुर। उच्चतम न्यायालय के द्वारा एस.सी. मेहता बनाम भारत संघ व अन्य के केस में दिए गए निर्णय की पालना में राज्य के गृह विभाग ने राज्य के दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में सम्पूर्ण वर्ष पटाखे चलाने, इसके निर्माण, संग्रहण, विक्रय (जिसेमें ऑनलाइन विक्रय भी शामिल है) और वितरण को प्रतिबंधित कर दिया है।

बुधवार को प्रस्तावित मॉक ड्रिल की तैयारियों समीक्षा की सी.एस. ने

जयपुर। वर्तमान परिदृश्य में राज्य में नागरिक सुरक्षा सुदृढ़ीकरण एवं क्रियाशीलता के आकलन हेतु केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा प्रदत्त दिशा निर्देशों की पालना में मंगलवार को मुख्य सचिव सुधांशु पंत को अध्यक्षता में राज्य के समस्त संभागीय आयुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, जिला कलेक्टर, जिला पुलिस अधीक्षक एवं सम्बन्धित जिला स्तरीय अधिकारियों की वीसी के माध्यम से बैठक आयोजित की गई। सचिवालय में आयोजित बैठक में बुधवार को प्रस्तावित मॉक ड्रिल एवं ब्लैक आउट हेतु संबंधित जिलों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। साथ ही यह भी निर्देशित किया गया कि सभी संघर्ष माध्यमों से सायरनों को तुरंत दुरुस्त किया जाकर संचार प्रणाली का सुदृढ़ीकरण सुनिश्चित किया जाए।

बैठक में गृह एवं आपदा प्रबंधन एवं नागरिक सुरक्षा, जल संसाधन एवं पीएचईडी के अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य व स्वायत्त शासन विभागों के प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा एवं उच्च शिक्षा व तकनीकी शिक्षा विभागों



केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा प्रदत्त दिशा-निर्देशों की पालना में मंगलवार को मुख्य सचिव सुधांशु पंत की अध्यक्षता में राज्य के समस्त संभागीय आयुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, जिला कलेक्टर, जिला पुलिस अधीक्षक एवं सम्बन्धित जिला स्तरीय अधिकारियों की वीसी के माध्यम से बैठक आयोजित की गई।

के शासन सचिव, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के आयुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव, पुलिस महानिदेशक राजस्थान, महानिदेशक इन्टेलिजेंस, महानिदेशक गृह रक्षा, प्रबंध निदेशक, जयपुर, अजमेर एवं

जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, प्रबंधक, उ.प. रेलवे जयपुर, कमाण्डेंट, राज्य आपदा प्रतिसाद दल, गुप कैप्टन, एयर फोर्स स्टेशन, महाप्रबंधक, भारत संचार निगम लिमिटेड, कमाण्डेंट छठी बटालियन

राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, एनसीसी निदेशक, जयपुर एयरपोर्ट निदेशक इत्यादि अधिकारियों उपस्थित थे। सभी अधिकारीगण ने बैठक में आपसी समन्वय से मॉक ड्रिल संपन्न करने हेतु प्रतिबद्धता जाहिर की।

‘कोई भी संदिग्ध भ्रष्टाचारी पाया गया तो दंडात्मक कार्यवाही होगी’



नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के मुख्य सतर्कता अधिकारी अमित कुमार शर्मा, वरिष्ठ एवं अतिरिक्त मुख्य सतर्कता अधिकारी तरुण कुमार जैन के द्वारा एनएफएल राज्य कार्यालय, जयपुर में भ्रष्टाचार के प्रति जागरूकता एवं रोकथाम पर समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

जयपुर। नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (एनएफएल) के मुख्य सतर्कता अधिकारी अमित कुमार शर्मा, वरिष्ठ एवं अतिरिक्त मुख्य सतर्कता अधिकारी तरुण कुमार जैन (मुख्य प्रबंधक, सतर्कता) के द्वारा एनएफएल राज्य कार्यालय, जयपुर में भ्रष्टाचार के प्रति जागरूकता एवं रोकथाम पर समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

बैठक में कंपनी के प्रति समर्पित

विभिन्न जिलों के थोक विक्रेताओ एवं राज्य कार्यालय राजस्थान के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भाग लिया। बैठक के दौरान अमित कुमार शर्मा, के द्वारा बैठक मे सम्मिलित एनएफएल के समस्त थोक विक्रेताओ, अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भ्रष्टाचार उन्मूलन के बारे मे विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई ताकि भ्रष्टाचार रहित संस्थान का उद्देश्य चरितार्थ हो एवं सभी को किसी भी

प्रकार की गतिविधियों मे भ्रष्टाचार न करने के लिए आदेशित किया गया। एनएफएल के समस्त थोक विक्रेताओं, अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भ्रष्टाचार विरोधी एवं सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा दिलाई गई। उन्होंने कहा कि कोई भी थोक विक्रेता, अधिकारी एवं कर्मचारी किसी भी प्रकार के अनैतिक भ्रष्टाचार संदिग्ध पाया गया तो उसके खिलाफ दंडात्मक एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

वारदात अंजाम देने से पहले हथियार सहित तीन बदमाश गिरफ्तार

पुलिस ने आरोपियों के पास से एक पिस्टल, छह जिंदा कारतूस और एक जीप बरामद की

अजमेर, (कासं)।हरिभाऊ उपाध्याय नगर थाना पुलिस और जिला स्पेशल टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए वारदात अंजाम देने से पहले हथियारों से लैस तीन बदमाशों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से एक पिस्टल, छह जिंदा कारतूस और एक जीप बरामद की गई है। पुलिस पूछताछ में मुख्य आरोपी भूपेंद्र सिंह खरवा खुद को कुख्यात लॉरिस बिश्नोई गैंग का सदस्य बताता है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

सीओ रुद्रप्रकाश शर्मा ने बताया कि जिला स्पेशल टीम को सूचना मिली थी कि हरिभाऊ उपाध्याय थाना क्षेत्र में कुछ बदमाश हथियारों के साथ घूम रहे हैं। इस पर पुलिस टीम ने पुष्कर घाटी पर नाकाबंदी की और एक संदिग्ध जीप को रोका। तलाशी लेने पर थार जीप से एक पिस्टल और छह कारतूस बरामद हुए। जीप में सवार तीनों युवक पुलिस को कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। शक



पुलिस और जिला स्पेशल टीम ने बदमाशों को गिरफ्तार किया।

के आधार पर पुलिस ने मौके से तीनों को गिरफ्तार कर लिया।

तीनों बदमाशों के खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज :-

सीओ शर्मा ने बताया कि गिरफ्तार

बदमाशों में ब्यावर निवासी भूपेंद्र सिंह खरवा, आदर्श नगर निवासी दीपक रावत और पीसांगन निवासी आदेश चौधरी हैं।

पुलिस की प्रारंभिक पूछताछ में

■ **पुलिस पूछताछ में मुख्य आरोपी भूपेंद्र सिंह खरवा ने खुद को कुख्यात लॉरिस बिश्नोई गैंग का सदस्य बताया**

■ **करीब पांच महीने पहले भी इन तीनों को मध्य प्रदेश पुलिस ने हथियारों के साथ गिरफ्तार किया था**

सामने आया कि आरोपी पुष्कर की ओर जा रहे थे और हथियारों की सप्लाई से जुड़े हैं। जानकारी में सामने आया है कि बदमाशों द्वारा हथियार जवाजा से खरीदे गए थे। गिरफ्तार तीनों आरोपियों के खिलाफ पहले से कई आपराधिक

मामले दर्ज हैं। करीब पांच महीने पहले भी इन तीनों को मध्य प्रदेश पुलिस ने हथियारों के साथ गिरफ्तार किया था।

लॉरिस बिश्नोई गिरोह से जुड़े तार :-सूत्रों के अनुसार भूपेंद्र सिंह खरवा का जुड़ाव सीधे तौर पर लॉरिस बिश्नोई गिरोह से है। भूपेंद्र पर इस गिरोह को हथियार सप्लाई करने का आरोप है। बताया जाता है कि वह वर्ष 2017 में पंजाब की एक जेल में अफीम तस्करी के मामले में बंद था, जहां उसकी मुलाकात लॉरिस से हुई थी। इसके बाद से ही वह गिरोह के लिए काम करने लगा। पुलिस ने तीनों आरोपियों को रिमांड पर लेकर गहन पूछताछ शुरू कर दी है। हैड कांस्टेबल सीताराम और कांस्टेबल रामनिवास की भूमिका महत्वपूर्ण भूमिका रही। पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कि इन बदमाशों के तार कहीं किसी बड़ी साजिश से तो नहीं जुड़े हैं।

मंदिर से अष्टधातु की राधा-कृष्ण की मूर्तियां चोरी



बबाई थाना क्षेत्र के कांकरिया गांव में मंदिर से चोर मुर्तियां चुराकर ले गये।

खेतड़ी, (निर्सं)। बबाई थाना क्षेत्र के कांकरिया गांव में मुख्य सड़क किनारे स्थित ठाकुरजी मंदिर में चोरों ने वारदात को अंजाम दिया है। चोर मंदिर से अष्टधातु की राधा-कृष्ण की प्राचीन मूर्तियां चोरी कर ले गए। घटना के बाद मंदिर के बाहर ग्रामीण एकत्रित हो गए तथा घटना की जानकारी पुलिस को दी गई।

मंदिर पुजारी यादराम ने बताया कि गांव में बना ठाकुरजी का मंदिर काफी समय पुराना है, जिसमें अष्टधातु की प्राचीन मूर्तियां स्थापित थी। मूर्तियों की ऊंचाई करीब डेढ़ फीट और वजन लगभग पांच किलो है। इनकी कीमत लाखों रुपये बताई जा रही है। मंदिर में ये मूर्तियां काफी वर्ष पहले स्थापित की

■ **घटना के बाद मंदिर के बाहर ग्रामीण एकत्रित हुए, पुलिस मौके पर पहुंची**

गई थी। चोरी की सूचना मिलते ही बबाई थाना प्रभारी कैलाश चंद्र मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का मौका मुआयना किया। मंदिर के पास ही संत परमानंद महाराज का स्थान है। यहां 6 मई को जागरण और 7 मई को मेला प्रस्तावित है। ग्रामीणों ने बताया कि मेले की तैयारियों के चलते मंदिर की मरम्मत चल रही थी। इसी कारण मंदिर का दरवाजा खुला हुआ था। इस संबंध में मंदिर के

पुजारी यादराम स्वामी ने थाने में रिपोर्ट दी कि वह शाम पूजा के बाद रात करीब साढ़े आठ बजे वे घर चले गए थे। सुबह छह बजे जब पूजा के लिए मंदिर पहुंचे तो मूर्तियां गायब थी। उन्होंने तुरंत गांव वालों को सूचना दी। घटना की जांच के लिए देवस्थान विभाग की टीम को भी सूचना दी गई है। मंदिर परिसर में कोई दरवाजा टूटा नहीं मिला। घटना के समय मंदिर में न पुजारी मौजूद था, न ही कोई चौकीदार था। थानाधिकारी कैलाश चंद ने बताया कि पुजारी की ओर से दी गई रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर लिया गया है, पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। इसके अलावा संदिग्ध लोगों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है।

बुजुर्ग को घर से बाहर निकाल लाठियों से पीटा

पाली, (निर्सं)। पाली में एक बुजुर्ग पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया, उसे बुरी तरह पीटा। घायल बुजुर्ग का कसूर सिर्फ इतना था कि उन्होंने गांव में एक शादी समारोह में अफीम की मनुहार किए जाने की शिकायत पुलिस-प्रशासन को दी थी। इससे नाराज लोगों ने शादी समारोह सम्पन्न होने के बाद बुजुर्ग को घर जाकर पीटा, जिससे वह घायल हो गया और उपचार के लिए उसे पाली के बांगड़ हॉस्पिटल में भर्ती कराया।

पाली के बांगड़ हॉस्पिटल में भर्ती घायल बुजुर्ग चिमनराम (62) पुत्र स्वरूपराम ने बताया कि वह सिरियारी थाना क्षेत्र के बेरा निम्बडिंडिया (चेलावास) गांव में रहता है। 11 अप्रैल को गांव में शादी हुई, जिसमें अफीम की मनुहार हुई। इसकी जानकारी उसने पुलिस-प्रशासन को दी। इससे नाराज

■ **घायल बुजुर्ग को उपचार के लिए पाली के बांगड़ हॉस्पिटल में भर्ती करवाया है**

■ **शादी समारोह में अफीम की मनुहार की पुलिस से शिकायत करने पर मारपीट की**

होकर उसके परिवार के लोगों ने कुछ ग्रामीणों के साथ मिलकर उस पर हमला कर दिया और घर से बाहर निकालकर लाठियों से पीटा, जिससे वह घायल हो गया। अपने साथ हुई घटना को लेकर उसने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

बार एसो. जहाजपुर ने कार्य बहिष्कार की चेतावनी दी

भीलवाड़ा, (निर्सं)। जिले के जहाजपुर बार एसोसिएशन ने पुलिस उपाधीक्षक नरेंद्र पारीक को ज्ञापन सौंपकर बताया कि मारपीट मामले में अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं होने पर अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार करेंगे।

बार एसोसिएशन अध्यक्ष दीपक चौहान ने बताया गया कि एसोसिएशन उपाध्यक्ष बद्रीलाल मीणा के साथ हुई मारपीट के मामले में थाना जहाजपुर

में प्रकरण संख्या 148/2025 दिनांक 5 मई को दर्ज किया गया था। आरोप है कि अभियुक्त, जो एक सरकारी कर्मचारी है, को थानाधिकारी द्वारा थाने में बुलाने के बाद बिना किसी कार्रवाई के छोड़ दिया गया। बार एसोसिएशन का कहना है कि घटना को गंभीरता से नहीं लिया गया है और आज तक न तो अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई है, न ही कोई ठोस कानूनी कार्यवाही की गई है। इस

नगर परिषद प्रशासन ने पुष्कर सरोवर में चार फव्वारे लगाए

फव्वारे पुष्कर सरोवर के मछलियां समेत जलीय जंतु के लिए जीवन देना वाला साबित हो रहे हैं



पुष्कर सरोवर में ऑक्सीजन लेवल एवं जल स्तर बढ़ाने के लिए फव्वारे लगाए गए हैं।

पुष्कर, (निर्सं)। बढ़ती तेज गर्मी को देखते हुए पुष्कर नगर परिषद प्रशासन ने पुष्कर सरोवर की तीन बन्द पड़े बोरिंग को चालू करवाकर तकनीकी प्रयोग के माध्यम से पानी के बड़े लंबे पाइप में छेद करके कम खर्च में ऑक्सीजन कंप्रेसर फव्वारे लगाए हैं। ये फव्वारे पुष्कर सरोवर के मछलियां समेत जलीय जंतु के लिए जीवन देना वाला साबित हो रहे हैं।

जानकारी के अनुसार पुष्कर नगर परिषद आयुक्त जगन्नाथ शर्मा ने बढ़ती तेज गर्मी को ध्यान में रखते हुए पुष्कर सरोवर की मछलियों एवं जलीय

जंतुओं को बचाने के लिए पुष्कर सरोवर के जल स्तर को बनाए रखने के लिए सप्त ऋषि घाट, जयपुर घाट और गुर्जर घाट पर बंद पड़े बोरिंगों को चालू करवाते हुए सरोवर का ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए तकनीकी अधिकारियों से बात की, जिस पर सफाई निरीक्षक लोकेंद्र सिंह द्वारा प्लंबर की सहायता से प्रेशर से बोरिंग के में छेद वाले बड़े पाइप फिट कर दिए जिससे बोरिंग का पानी प्रेशर से आने के चलते फव्वारे के माध्यम से सरोवर में जल गिर रहा है और पुष्कर सरोवर का ऑक्सीजन लेवल भी बढ़ रहा है और यह कम खर्च

में कंप्रेसर पाइप बन गया है जिससे पुष्कर सरोवर की मछलियां एवं जलीय जंतुओं के लिए बरदान साबित हो रहा है। वहीं पुष्कर नगर परिषद प्रशासन नेगत महीने पहले पुष्कर सरोवर का ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए पांच कंप्रेसर ऑक्सीजन फव्वारे लगवाए थे। पांच कंप्रेसर अब नगर परिषद प्रशासन की देखरेख में चल रहे हैं जिससे भी लगातार पुष्कर सरोवर के जलीय जंतुओं को आक्सीजन देने के कार्य में जुटा हुआ है। नगर परिषद प्रशासन की ओर से कंप्रेसर फव्वारे की देखरेख के लिए चार कर्मचारी रखरखाव के लिए लगा रखे हैं।

कार में बैठी सैलानी युवती ने 70 साल के बुजुर्ग को फंसाया

जैसलमेर, (नि.सं.)। जिले के सरहदी तनोट थाना क्षेत्र में सैलानी ने भेड़-बकरी चराने वाले 70 वर्षीय बुजुर्ग को बहला फुसलाकर अश्लील हरकतें की, जिसका शर्मनाक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। ग्रामीणों ने प्रशासन से पर्यटक स्थलों पर आ रहे ऐसे अश्लील लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

गौरतलब है कि जैसलमेर घूमने

आई महिला ने न सिर्फ बुजुर्ग के साथ अश्लील वीडियो वेबसाइट पर अपलोड किया है। साथ ही सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर जैसलमेर के पर्यटन स्थलों पर नग्न तस्वीरों भी खींच कर पोस्ट की है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद जिले की तनोट थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने आमजन से अपील की है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर

अनावश्यक वीडियो वायरल नहीं करें। फिर भी यदि किसी के द्वारा उक्त वीडियो वायरल करने की जानकारी मिलती है तो इसकी सूचना पुलिस को दें। वायरल वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि एक गाड़ी में एक महिला और उसके साथी बैठे हैं। सरहदी क्षेत्र में सुनसान जगह पर गाड़ी रोककर भेड़-बकरी चरा रहे एक बुजुर्ग को अपने पास बुलाते हैं और अश्लील हरकतें करते हैं।

कैथून सीएचसी का निरीक्षण कर व्यवस्थाएं जांची

कोटा, (निर्सं)। सीएचसी कैथून प्रभारी डॉ. राजेश सामर ने बताया कि संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं जॉन कोटा डॉ. एमपी सिंह ने मंगलवार को सीएचसी कैथून का औचक निरीक्षण किया।

इस दौरान संयुक्त निदेशक डॉ.एमपी सिंह ने लू तापघात के प्रभाव एवं मौसमी बीमारियों को देखते हुए चिकित्सालय में की जा रही तैयारियां जांची। निरीक्षण के दौरान लू-तापघात के लिए आरक्षित किए गए बेड चैक किए। वार्ड में मरीजों से जानकारी ली।

साथ ही लेब में सीबीनाट मशीन से कम हो रही स्ट्रुटम जांचों की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए। इसके बाद उन्होंने जननी सुरक्षा वार्ड, एनबीएसयू, लेबररूम, दवा भंडार कक्ष का भी निरीक्षण किया। सीएचसी पर उपलब्ध हो यह सुनिश्चित किया जाए। इसके बाद मरीजों के लिए की गई पीने के पानी की व्यवस्था को भी देखा। साथ ही ऑनलाइन निरीक्षण प्रप्रज भी भरा।

पुष्कर में मुख्य परिक्रमा मार्ग पर गंदा पानी भरा होने से श्रद्धालु परेशान



परिक्रमा मार्ग में भरे गंदे पानी से वाहन चालक परेशान हो रहे हैं।

■ **पुष्कर सरोवर में आगामी आठ मई से पंच तीर्थ स्नान का शुभारंभ होगा**

■ **धार्मिक आस्था के चलते पुष्कर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ना शुरू हुई**

धार्मिक महत्व के चलते वैशाख माह में पुष्कर सरोवर में डुबकी लगाकर पुण्य कमाने और धार्मिक आस्था के चलते पुष्कर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ना शुरू हो गई है।

धीषण गर्मी के बाबजूद रोजाना हजारों श्रद्धालु पुष्कर पहुंच रहे हैं। पंचतीर्थ स्नान के लिए हजारों श्रद्धालु पवित्र सरोवर में डुबकी लगाकर जगत्पिता ब्रह्मा मंदिर के दर्शन कर पुण्य लाभ अर्जित करेंगे। कार्तिक के बाद

गर्मी से बचाव के लिए नगर परिषद व स्थानीय भागमशाहों व्यापारिक व सामाजिक संगठनों द्वारा शीतल पेयजल नींबू पानी शरबत व छाया के लिए इंतजाम किए जाएंगे।

परिक्रमा मार्ग में भरा गंदा पानी आस्था पर डेस :-सरोवर की परिक्रमा का धार्मिक कर्म संपादित करने वाले श्रद्धालुओं को गंदे पानी से गुजरना पड़ रहा है जिससे उनकी आस्था आहत हो रही है। लोगों ने मांग की है कि गुरुवार से शुरू होने वाले वैशाख पंच तीर्थ मेले में हजारों श्रद्धालु परिक्रमा करेंगे इससे पूर्व परिक्रमा मार्ग के जल भराव को दुरुस्त कर अवरुद्ध मार्ग को खोला जाए। पांच दिवसीय वैशाख मेले में रावत व गुर्जर समाज के श्रद्धालु तीर्थ नगर पुष्कर आते हैं और गुर्जर समाज का प्रसिद्ध आस्था केंद्र भुनाजी का मंदिर व गुर्जर घाट का एकमात्र रास्ता भी परिक्रमा मार्ग के जल भराव से होकर ही गुजरता है।

भिवाड़ी/कोटपुतली, (निर्सं)। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े मंगलवार को खैरथल-तिजारा जिले के भिवाड़ी रीको गेस्ट हाउस में समीक्षा बैठक लेने पहुंचे। राज्यपाल हरिभाऊ के भिवाड़ी पहुंचने पर जिले के कलेक्टर किशोर कुमार व भिवाड़ी एसपी ज्येष्ठा मैत्रेयी ने स्वागत कर अंगवानी की। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने गरीब किसान के जन-कल्याण की योजनाओं, कानून व्यवस्था व बजट घोषणाओं पर हुए विकास के कार्यों पर चर्चा कर समीक्षा की व अधिकारियों को निर्देशित किया और कहा कि समावेशी आर्थिक विकास तभी संभव है “जब हर हाथ को काम और हर व्यक्ति को आय” का अवसर मिले, यही आत्मनिर्भरता की सच्ची दिशा है।

राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने योजनाओं के समयबद्ध, प्रभावी और परिणामोन्मुखी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए अधिकारियों से कहा कोई भी पात्र व्यक्ति योजनाओं के लाभ से वंचित नहीं रहना चाहिए, योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाए, ताकि उनका लाभ समाज के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक पहुंच सके और वास्तविक जरूरतमंद वर्ग सशक्त हो सके। उन्होंने विभिन्न योजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। जिले में हीट वेव के संबंध में की गई तैयारियों एवं स्वास्थ्य सेवाओं और सूचकांकों की समीक्षा करते हुए पोषण



राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने भिवाड़ी के रीको गेस्ट हाउस में समीक्षा बैठक ली।

कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन पर बल दिया। राज्यपाल ने कहा कि समावेशी आर्थिक विकास की दिशा में सार्थक पहल तभी संभव है जब समाज के हर वर्ग को सम्मानजनक रोजगार और आय के अवसर उपलब्ध कराए जाएं। उन्होंने कहा कि “हर हाथ को काम और हर व्यक्ति को आय” की भावना को आत्मनिर्भर भारत की नींव मानते हुए हमें नीतियों और योजनाओं को जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू करना चाहिए।

ग्रामीण क्षेत्रों में राजीविका और सहकारिता विभाग की योजनाओं के माध्यम से सशक्त बने समूहों की सराहना करते हुए कहा कि इन

योजनाओं के माध्यम से समाज के अंतिम व्यक्ति तक आर्थिक सशक्तिकरण की रोशनी पहुंचे इस दिशा में कार्य किया जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में जल उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए ड्राई जेन में टैकरी के माध्यम से पानी सप्लाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने जल जीवन मिशन की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिले में प्रत्येक घर तक नल कनेक्शन की पहुंच सुनिश्चित की जाए, साथ ही उनकी कार्यात्मक स्थिति भी सुनिश्चित की जाए तथा योजना के तहत शेष रहे गांवों में त्वरित रूप से योजनांतर्गत कार्य करते हुए पानी की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। उन्होंने

पंचायती राज विभाग द्वारा चलाई जा रही मनरेगा योजना की समीक्षा करते हुए पात्र व्यक्तियों को योजना से लाभान्वित करने के निर्देश दिए। राज्यपाल ने अभियान हरियालो-राजस्थान राजस्थान के तहत जिलेभर में सामूहिक वृक्षारोपण कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि केवल पौधारोपण ही नहीं, बल्कि आगामी वर्षों तक इन वृक्षों के संरक्षण और समुचित रखरखाव की ठोस व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, ताकि लगाए गए हर पौधे को पेड़ बनने का अवसर मिले और पर्यावरण संरक्षण का लक्ष्य साकार हो सके। उन्होंने शिक्षा को मानव कल्याण का सशक्त माध्यम बताते हुए विद्यालयों

एवं छात्रावासों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कृषि विभाग को निर्देश दिए कि मृदा परीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत किसानों को अधिक से अधिक जागरूक किया जाए, ताकि वे स्वयं अपनी भूमि की मृदा जांच कराएं और वैज्ञानिक पद्धति से खेती कर उत्पादन एवं आय में वृद्धि कर सकें। उन्होंने फार्म पॉन्ड, फसल बीमा योजना के तहत अधिक से अधिक किसानों को लाभान्वित करने के निर्देश दिए। राज्यपाल ने जिले में चलाए जा रहे निराश्रित गोवंश को आश्रय अभियान नवाचार की सराहना की और अधिकारियों को निर्देश दिए कि ग्रीष्मकाल में बेसहारा पशुओं के लिए पानी, छाया और चारे की समुचित व्यवस्था भी साथ में सुनिश्चित की जाए। सहकारिता की भावना को स्पष्ट करते हुए कहा कि इसका उद्देश्य लाभ या हानि नहीं, बल्कि किसान और आमजन को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाना है। यही सहकारिता की सच्ची सफलता है।

बैठक में अतिरिक्त कलेक्टर किशोर कुमार, एसपी भिवाड़ी ज्येष्ठा मैत्रेयी, पुलिस अधीक्षक खैरथल मनोष कुमार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी बीड़ा अतुल प्रकाश, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सालुखे गौरव रविंदर, अतिरिक्त जिला कलेक्टर भिवाड़ी सुमित्र मिश्र सहित जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।

